● वर्ष-5

● अंक-163

रायपुर, शनिवार
21 फरवरी 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6› सेहत के लिए बेहद लाभकारी ...

मुख्यमंत्री साय का 62वाँ जन्मदिन 'सेवा-सुशासन-संकल्प दिवस' के रूप में मनाया जाएगा

■ भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने कार्यक्रमों की जानकारी दी, कहा : मुख्यमंत्री के विजन 'सुशासन' को जन-जन तक पहुँचाना और अंतिम व्यक्ति की सेवा करना ही आयोजन का उद्देश्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 62वें जन्मदिवस को इस वर्ष पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक और सेवाभावी उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय ने बताया कि इस विशेष अवसर को 'सेवा-सुशासन-संकल्प दिवस' के रूप में समर्पित करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के जन्मदिन को जन-सेवा से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में फल वितरण किया जाएगा। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान और मुख्यमंत्री

श्री साय के पर्यावरण प्रेम को देखते हुए राज्यभर में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम जनमानस की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ विशेषज्ञों द्वारा जाँच और दवाइयों का वितरण होगा। सुशासन के संकल्प को दोहराने के लिए जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन होगा।

भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने बताया कि भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को इस निमित्त अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। प्रत्येक मोर्चा अपनी विशिष्ट कार्ययोजना के अनुसार इस दिन को यादगार बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहेगा। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री श्री साय के विजन 'सुशासन' को जन-जन तक पहुँचाना और अंतिम व्यक्ति की सेवा करना है। श्री साय के 62वें जन्मदिवस पर पार्टी कार्यकर्ता गरीब कल्याण और छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित किया हैं।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकसित राज्य बनने को अग्रसरः किरण देव

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन को भाजपा परिवार द्वारा सेवा-सुशासन-संकल्प दिवस मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। आज प्रदेश का हर वर्ग किसान, महिला, युवा, सभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। देव ने कहा कि कल 21 फरवरी को मुख्यमंत्री साय का 62वां जन्मदिन है जिसको लेकर भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री साय के जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है।

जन्म शताब्दी पर डिप्टी सीएम साव का ऐलान

छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने पद्मश्री चतुर्वेदी का सपना होगा पूरा

बिलासपुर। राज्य के डिप्टी सीएम अरूण साव ने कहा है कि पद्मश्री पं श्यामलाल चतुर्वेदी का सपना पूरा करने, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए जो कुछ ?भी करने की जरूरत होगी वह हम सब मिलकर करेंगे. शुक्रवार को बिलासपुर में पं चतुर्वेदी की जन्म शताब्दी लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में उप मुख्यमंत्री साव के मुख्य आतिथ्य और दिल्ली, रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने की अध्यक्षता में समारोहपूर्वक मनाई गइ।

इस मौके पर पं चतुर्वेदी पर वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी के संपादकत्व में प्रकाशित स्मृति ग्रंथ और पं चतुर्वेदी की छत्तीसगढ़ी पुस्तिका 'भोलवा भोलाराम बनिस'का डॉ. सुषमा शर्मा द्वारा प्रकाशित हिंदी अनुवाद का विमोचन किया गया. कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, नगर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित जन्म शताब्दी समारोह समिति के पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य साहित्यकार एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे.

उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि 2 अप्रैल 2018 को जब चतुर्वेदी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो लगा कि यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता को सम्मान मिला हो. वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कवि भी थे, साहित्यकर व पत्रकार थे और बेबाक अंदाज में बोलते थे.

छत्तीसगढ़ी संस्कारों से पगे

उन्होंने कहा कि पं चतुर्वेदीजी 100 प्रतिशत छत्तीसगढ़ी संस्कार से पगे हुए थे. जिस प्रकार उन्होंने अनवरत साहित्य साधना की , जीवन जीया, हम सबके लिए प्रेरणादायी है. साव ने कहा कि पं चतुर्वेदी की स्मृति को अक्षुण रखने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने जो जो हो पाएगा, वह सब कुछ करेंगे।

अप्रतिम योगदान

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि पं. श्यामलाल चतुर्वेदी ने जीवन पर्यंत छत्तीसगढ़ की माटी, भाषा और लोक संस्कारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया. वे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे और छत्तीसगढ़ी भाषा के संवर्धन में उनका योगदान अविस्मरणीय है. जीवन पर्यंत उन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी, भाषा और संस्कारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है. छत्तीसगढ़ सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दूरसंचार नेटवर्क एआई से होंगे और स्मार्ट, पारदर्शी एवं सुरक्षितः ट्राई अध्यक्ष

नईदिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब टेलीकॉम सेक्टर में कोई अतिरिक्त तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि यह नेटवर्क के डिजाइन, संचालन और उपभोक्ता अनुभव का आधार बन चुकी है। जिम्मेदार एआई से उपभोक्ता भरोसा और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा।

ट्राई के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शुक्रवार को यहां सुषमा स्वराज भवन में दूरसंचार में जिम्मेदार एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में, जहां 1.2 अरब से ज्यादा मोबाइल ग्राहक और लगभग एक अरब डेटा उपयोगकर्ता हैं, वहां एआई आधारित ऑटोमेशन अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरी हो गया है। कार्यक्रम में सरकार के प्रतिनिधि, वैश्विक तकनीकी

कंपनियों के नेता, टेलीकॉम सेवा प्रदाता और अंतरराष्ट्रीय नीति समुदाय के सदस्य शामिल रहे।अध्यक्ष ने बताया कि एआई का इस्तेमाल नेटवर्क प्रदर्शन सुधारने, खराबी का पूर्वानुमान लगाने, ऊर्जा बचाने, ग्राहक अनुभव बेहतर करने और स्पैम व धोखाधड़ी रोकने में किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि स्पैम कॉल और संदेशों पर कार्रवाई के तहत 21 लाख से ज्यादा नंबर बंद किए गए हैं और एआई व ब्लॉकचेन आधारित फिल्टरिंग से शिकायतें घटकर प्रति करोड़ कॉल और एसएमएस पर लगभग एक तक रह गई हैं।

उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल जितना बड़ा होता है, उसका असर भी उतना ही व्यापक होता है। इसलिए पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी है।

ट्राई ने 2023 में एआई और बिग डेटा के इस्तेमाल पर सिफारिशें जारी की थीं, जिसमें जोखिम आधारित नियामक ढांचा सुझाया गया था। 2024 में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की सिफारिशें भी दी गईं, ताकि 5जी और भविष्य की 6जी नेटवर्क पर एआई आधारित समाधान सुरक्षित माहौल में परखे जा सकें।

अध्यक्ष ने कहा कि आज की दो मुख्य सत्र इसी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। पहला सेशन नेटवर्क को एआई युग के लिए तैयार करने पर केंद्रित है, जबकि दूसरा सेशन ग्राहक भरोसा बनाने और एआई आधारित संचालन में पारदर्शिता व नैतिकता पर चर्चा करेगा। भारत का अनुभव वैश्विक स्तर पर उपयोगी साबित हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से साझा चुनौतियों का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि एआई टेलीकॉम का भविष्य तय करेगा।

मोदी-गुटेरेस ने एआई को समावेशी बनाने में यूएन की भूमिका पर की चर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समावेशी बनाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट में बताया कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को लेकर चर्चा की, जिनका उद्देश्य एआई को सभी के लिए लाभकारी और सुलभ बनाना है।

एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन देश की छवि धूमिल करने की साजिशः भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने एआई समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह देश की छवि धूमिल करने की साजिश है।भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉ. संबित पात्रा ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी बारकोड लेकर कार्यक्रम के भीतर प्रवेश कर गए थे और उन्होंने विरोध स्वरूप अपनी टी-शर्ट उल्टी पहनी हुई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट चल रहा है, जिसमें युवा कांग्रेस के चार लोग गिरफ्तार हुए हैं।

प्रमुख समाचार

घाटा बता कर जनता से वसूला जा रहा है : दीपक बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार को बिजली विभाग की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह सरकार लाइन लॉस और बिजली चोरी रोक नहीं पा रही है, सरकारी विभागों पर ही करोड़ों का बिल भुगतान बकाया है, भाजपा के नेता मंत्री और अधिकारी बिना

भुगतान किए अनियंत्रित उपभोग कर रहे हैं, बिजली विभाग सरकारी कार्यालयों से बिल वसूली नहीं कर पा रही है, अब सरकारी दफ्तरों और शासकीय भवनों से बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए प्रीपेड बिलिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है, इससे साफ है कि यह सरकार, सरकारी अनियमितताओं पर सरेंडर मोड पर है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि एक तरफ यह सरकार बार-बार बिजली के दाम बढ़ा कर उपभोक्ताओं की जेब ढीली कर रही है, घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना खत्म कर दिया है। आम जनता यदि एक माह बिल जमा न कर पाए तो बिजली काट दी जाती है, लेकिन उन्हीं बिजली कंपनियों का सरकारी विभागों पर 2,800 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है।

23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र

रायपुर। आम बजट के बाद अब छत्तीसगढ़ की जनता को प्रदेश के बजट का इंतजार है. इस बीच 23 फरवरी से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी

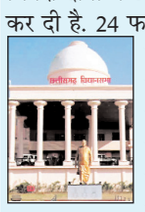

वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. उससे पहले बैठकों प्रेस वार्ताओं और रणनीतिक मंथन का दौर तेज हो गया है.छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से प्रारंभ होगा. पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का खाका पेश किया जाएगा. 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे. यह सत्र 20 मार्च तक चलेगा और कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं. प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है.विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 21 फरवरी को अपने शंकर नगर स्थित शासकीय निवास में पत्रकार वार्ता बुलाई है. इस दौरान वे बजट सत्र की कार्यवाही, नियमों और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत जानकारी देंगे।

भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को हड़ताल गढ़ बना दियाः ठाकुर

रायपुर। भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी करने एवं जनता की आवाज को नहीं सुनने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार अपने वादाखिलाफी एवं जन विरोधी रवैया के चलते अलोकप्रिय हो चुकी है। हर वर्ग में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, गहरी

नाराजगी है। भाजपा ने प्रदेश को हड़ताल गढ़ बना दिया है, जहां हर कोई अपनी समस्या का हल नहीं होना एवं भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर शासकीय कर्मचारी हड़ताल कर रहे है, तो कांग्रेस भी लगातार जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रही है, अन्य वर्ग चक्का जाम कर मंत्री निवास व कलेक्ट्रेट घेराव कर, आंदोलन कर रहे है। सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश व उठ रही आवाज से घबराई भाजपा सरकार अब अंग्रेजों की तरह दमनकारी कार्यवाही कर रही है। पुलिस तंत्र का उपयोग कर आंदोलनकारियों पर लाठियां चलवा रही है, उन्हें जेल में बंद कर रही है, डरा-धमका रही, फर्जी मुकदमे दर्ज कर लोकतंत्र के अधिकारों का दबावपूर्वक हनन कर रही है। राजधानी रायपुर का धरना स्थल तुता में विभिन्न संगठनों के आंदोलनों के कारण जगह छोटा पड़ जा रहा है। 24 घण्टा वहां धरना प्रदर्शन हो रहा है।

भाजपा सरकार ने हर वर्ग को ठगा है: वर्मा

रायपुर। भाजपा सरकार पर वादाखिलादी का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि इस सरकार ने मोदी की गारंटी के नाम पर हर वर्ग को ठगा है, किसान अपना पूरा धान बेच नहीं पाए, युवा बेरोजगारी की

मार झेल रहे हैं, महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, महिला समूहों को काम नहीं मिल रहा है, 26 महीनों की भाजपा सरकार से हर वर्ग को केवल निराशा हाथ लगी है। कानून व्यवस्था बदहाल है, वर्ग संघर्ष चरम पर है, यह सरकार छत्तीसगढ़ को एक और मणिपुर में बदलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आबादी के हर वर्ग को ठगा हुआ और अपमानित महसूस कराया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आज कोई भी जाति, वर्ग या समाज ऐसा नहीं बचा है जो भाजपा सरकार के शासन में अपमानित महसूस न कर रहा हो। आदिवासियों से जल, जंगल, जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं, संसाधनों की लूट मची है, बलौदाबाजार मामले में सतनामी समाज को प्रताड़ित किया गया।

गरीब बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहती सरकारः साहू

रायपुर। प्रदेश में भारतीय संविधान में 86वें संशोधन (2002) के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, जो अनुच्छेद 21 के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ और इसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

लाया गया, इस अधिकार को आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार चौतरफ़ा अनदेखी कर रही है। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की बदहाल स्थिति और शिक्षा फंड में कटौती,गरीब बच्चों की आरटीई सीटों की समाप्ति और शिक्षकों की वरीयता को नज़र अंदाज कर सीधी भर्ती को लेकर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए पत्रकार वार्ता की । पत्रकार वार्ता में प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने बताया कि आत्मानंद स्कूलों को मिल रहे फंड में कटौती, कई स्कूलों के बंद होने की आशंका, शिक्षकों की कमी, बिजली बिल बकाया, संसाधनों के अभाव और बच्चों को ड्रेस-किताबें न मिलने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

आम आदमी पार्टी पर पंजाब की जनता का भरोसा बरकरार रहेगा?

इकबाल सिंह चन्नी

2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व पर बहुत भरोसा जताया और उसके उम्मीदवारों को रिकॉर्ड संख्या में जिताया। पंजाब के चुनावी इतिहास में यह पहली बार हुआ, जब एक ही पार्टी के 92 उम्मीदवार, वह भी ऐसी पार्टी, जिसकी लीडरशिप को किसी भी तरह से परखा नहीं गया था, जीत कर विधायक बने। इस तरह पंजाब में 'आप' की सरकार बनी और लोगों को उम्मीद होने लगी कि जल्द ही उनकी परेशानियां हल हो जाएंगी और 'आप' की गारंटी पूरी होने से उनकी जिंदगी आरामदायक हो जाएगी।क्योंकि 'आप' के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 22 के चुनाव से पहले पंजाब के लोगों को कई गारंटियां दीं और कई वादे किए थे। 'आप' सरकार ने जल्द ही लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का अपना वादा पूरा किया और दावा किया कि 'आप' सरकार की वजह से पंजाब के 80 प्रतिशत लोगों का बिजली बिल जीरो हो गया है।

लेकिन बाकी गारंटियां और वादे, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देना, बेअदबी के मामलों में 24 घंटे में इंसाफ, 3 महीने में नशा खत्म करना, वी.आई.पी. कल्चर खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करके सरकारी खजाने में सालाना 34,000 करोड़ रुपए जमा करना, रेत माफिया को खत्म करके 20,00 करोड़ रुपए तथा शराब पॉलिसी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करके पंजाब की आर्थिक हालत सुधार कर पंजाब को कर्ज के जाल से बाहर निकालना, सेहत और शिक्षा व्यवस्था को नंबर 1 पर लाना, कानून व्यवस्था सुधारने और पंजाब में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाकर युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और विदेश जाने की जरूरत खत्म करने जैसे वादे किए गए थे।

भगवंत मान सरकार इनमें से ज्यादातर गारंटियां और वादे पूरे करने में नाकाम रही, हालांकि युवाओं को सरकारी नौकरियां देने में काफी हद तक सफल रही लेकिन विपक्ष यह भी सवाल उठाता है कि सरकार यह क्यों नहीं बताती कि इन 4 सालों में कितने कर्मचारी रिटायर हुए हैं। सरकार के ये आंकड़े जारी न करने की वजह से

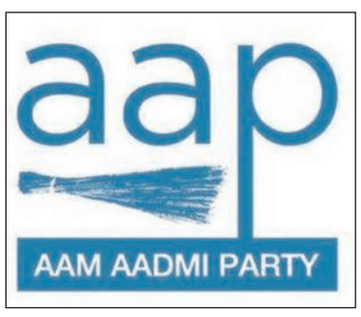

विपक्ष का दावा है कि रिटायरमैंट दर 5 से 9 प्रतिशत है और आरोप है कि 'आप' सरकार ने उतने युवाओं को नौकरी नहीं दी, जितने रिटायर हुए हैं। इन्हीं वजहों से 2 साल बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 'आप' को 22 के मुकाबले बहुत कम रिस्पॉन्स मिला। इन चुनावों में 'आप' का वोट शेयर 41 से घटकर करीब 26 प्रतिशत रह गया और पार्टी के सिर्फ 3 उम्मीदवार ही जीत पाए, जबकि 'आप' के 2 उम्मीदवार आजाद के तौर पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे।

इसके अलावा, कुछ ही महीने बाद 2022 में भगवंत सिंह मान अपने ही चुनाव क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान से हार गए। इन चुनावों के नतीजों से सीख लेकर 'आप' ने आत्ममंथन शुरू किया और पार्टी के काम करने के तरीकों में भी बदलाव किए। उसने कई तरह के कैंपेन भी चलाए। इनमें पंजाब को एक मॉडल राज्य के तौर पर पेश करना, रैवेन्यू डिपार्टमैंट पर शिकंजा कसना, बुलडोजर चलाना, महिलाओं को 1000 रुपए समेत बाकी गारंटियां और वादे पूरे करने का भरोसा दिलाना, पार्टी में अनुशासन लाना और अब ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के अलावा और भी कई कोशिशें की जा रही हैं।

हालांकि इसी भरोसे की वजह से पार्टी को पिछले दिनों हुए उपचुनाव और स्थानीय चुनावों में कामयाबी मिली लेकिन इन जीतों को विधानसभा चुनाव जीतने की गारंटी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर पंजाब के पिछले राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि पंजाब के लोग भरोसा करने में तो माहिर होते हैं लेकिन जब उनके भरोसे पर थोड़ी-सी भी चोट लगती है, तो वे भरोसा छोड़ भी देते हैं, जिसके 2 हालिया उदाहरण हमारे सामने हैं।

पहला, अकाली-भाजपा सरकार का बदलना। हालांकि पंजाबियों को अकाली-भाजपा सरकार के किए गए विकास से कोई एतराज नहीं था लेकिन धार्मिक मामलों में की गई गलतियों और ड्रग्स नियंत्रण के मुद्दे पर पंजाबियों का विरोध झेलना पड़ा, जिसकी वजह से अकाली दल और भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह, कांग्रेस सरकार, जो ड्रग्स खत्म करने, किसानों का कर्ज माफ करने और विकास के वादे की वजह से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, उसे भी पंजाबियों ने 2022 में बाहर कर दिया। लेकिन 'आप' की सरकार इन तीनों पार्टियों से ज्यादा और बड़े वादे करके आगे आई थी। अब पंजाबी फिर से सोचने लगे हैं कि किस पार्टी ने पंजाबियों से किए वादे पूरे किए।

छुट्टी पर घर लौट रहा आईटीबीपी का जवान हुआ लापता

गोरखपुर में मिला सामान, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। पंजाब में तैनात आईटीबीपी का एक जवान छुट्टी पर घर लौटते समय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। जवान ने 7 फरवरी की रात परिजनों से फोन पर रायपुर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यूपी के गोरखपुर में उनका सामान मिलने से मामला और भी रहस्यमय हो गया है।

चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम कसावाही निवासी जवान विनोद कुमार गोटी वर्तमान में पंजाब के लुधियाना स्थित आईटीबीपी पोस्ट पर पदस्थ है।

जानकारी के अनुसार, 7 फरवरी की रात करीब 10 बजे उन्होंने परिजनों से फोन पर बातचीत कर बताया था कि वे छुट्टी लेकर घर लौट रहे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद उन्हें लेने आने के लिए कहा था। अगली सुबह जब उनके पिता ने संपर्क करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल फोन बंद मिला।

परिजनों ने लगातार संपर्क करने का प्रयास किया इसी बीच रेलवे पुलिस गोरखपुर ने कॉल रिसीव कर जानकारी दी कि जवान का रेलवे से संबंधित सामान गोरखपुर में मिला है, जिसे छोड़कर वे कहीं चले गए हैं। सूचना मिलते ही चिंतित परिजन गोरखपुर पहुंचे, लेकिन वहां भी जवान का कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजन उनका सामान लेकर वापस कांकेर लौट आए हैं।

घटना के बाद से जवान विनोद कुमार गोटी की तलाश जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। जवान के अचानक लापता हो जाने से परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच कर जल्द से जल्द जवान का पता लगाया जाए।

सीजी बोर्ड 12वीं परीक्षा शुरू छात्र-छात्राओं में उत्साह

जीपीएम। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजी बोर्ड) की हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (12वीं) परीक्षा कल से जिले में शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आई। प्रशासन द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हुई। परीक्षा केंद्रों में, पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

नकल पर रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय 3 उड़नदस्ता टीमें गठित की गई हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों में भी निगरानी के लिए उड़नदस्ता टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करेंगी। परीक्षा के पहले दिन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और उत्साह देखने को मिला। अभिभावक भी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते नजर आए।

झीरम घाटी में शहीद कांग्रेस नेताओं को जवान दे रहे सच्ची श्रद्धांजलि: विजय शर्मा

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा गुरुवार को एक दिवसीय कवर्धा विधानसभा के दौर पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झीरम में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को उनकी सरकार सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि देश का 80 प्रतिशत नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में था। बड़ी संख्या में जवान जंगलों की खाक छानते थे। लेकिन अब 6 हजार नक्सलियों में से सिर्फ 300 नक्सली ही बचे है, वो भी जल्द समाप्त होंगे।

विजय शर्मा ने कहा कि सही मायनों में कांग्रेस के नेताओं की शहदात का बदला भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलियों को मिटाकर किया है। विजय शर्मा ने झीरम घाटी में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को याद करके कहा कि कांग्रेस शहीदों को अपना कहती हैं लेकिन आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया जबकि नक्सलियों को खत्म करके शहीद कांग्रेस नेताओं को जवान सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 23 फरवरी से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ बजट सत्र को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार के बजट में सब कुछ खास है। इस बार एक महीने का बजटसत्र चल रहा है। बजट भी पेश होगा और बहुत सारे जरूरी विधयेक भी पेश किए जाएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा दौरे के दौरान ग्राम बम्हनी में 20 लाख की लागत से बनने वाले लोधी सामाजिक भवन का भूमिपूजन किया। इस दौरान गांव के सरपंच समेत लगभग 100 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। कार्यक्रम के बाद डिप्टी विजय शर्मा ग्राम बैहरसरी पहुंचे और वहां 12.63 करोड़ की लागत से 3 नई सड़कों का भूमिपूजन किया। इस सड़क के बनने से तीन अलग-अलग गांव बैहरसरी से मुख्य मार्ग तक 8।80 किलोमीटर, मदनपुर से बटूराकछारों 1।40 किलोमीटर और खडौदा से मदनपुर तक 3।40 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण होगा। जिससे गांव के लोगों का आवागमन सुगम होगा और गांव के विकास को मजबूती मिलेगी। डिप्टी सीएम ने बैहरसरी में समुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं कवर्धा पहुंच कर विजय शर्मा ने शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया, इस दौरान जनप्रतिनिधि, चन्द्रवंशी समाज पदाधिकारी समाज के लोग, भाजपा कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

अवैध उत्खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की सख्ती

पोकलेन समेत 16 वाहन किए जब्त

जगदलपुर। बस्तर जिले में अवैध उत्खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग के द्वारा अभियान चलाया गया। खनिज विभाग के जांच दल ने पिछले 9 दिनों के भीतर छापेमारी कर अवैध गतिविधियों में संलिप्त 16 वाहनों को जब्त किया है। खनिज विभाग की कार्रवाई के दौरान रेत, चूना पत्थर और लाल ईंट का अवैध रूप से परिवहन कर रहे ट्रैक्टर, हाइवा और टिप्परों को जब्त किया गया। वाहन ग्राम कंगोली, परपा, बालेंगा, लालबाग और पल्लीनाका जैसे क्षेत्रों से गुजर रहे थे। इसके अलावा मूतनपाल क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन करते हुए एक चेन माउंटेड पोकलेन मशीन को भी जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया है। अवैध उत्खनन और परिवहन के सभी 16 प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 और खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

विश्वास और बदलते बस्तर की नई पहचान

- रिवर एडवेंचर फेस्ट के जरिए नक्सलगढ़ के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

बीजापुर। बीजापुर जिले के मट्टीमरका में इंद्रावती नदी के तट पर रिवर एडवेंचर फेस्ट आयोजित किया गया। जिसमें नक्सलगढ़ के युवाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। जिससे यह फेस्ट केवल एक साहसिक खेल आयोजन नहीं, बल्कि बदलते बस्तर और उभरते विश्वास की नई पहचान बनकर सामने आया। जिला प्रशासन बीजापुर की पहल पर आयोजित इस फेस्ट में दूरस्थ और आदिवासी बहुल गांवों के बच्चों व युवाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और आत्मविश्वास का माहौल दिखाई दिया। कभी भय और अलगाव की छाया में रहे इस अंचल में अब विकास, रोमांच और नए अवसरों की रोशनी नजर आने लगी। फेस्ट के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके भीतर छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त प्रयास किया गया। आयोजन स्थल पर जिपलाइन, बंजी जंपिंग, जुमरिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एटीवी राइड, तीरंदाजी, बीच वॉलीबॉल और रिवर कैंपिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों ने प्रतिभागियों को साहसिक खेलों से परिचित कराया। रात में स्टार गेजिंग और दिन में स्थानीय बस्तरिया व्यंजनों ने आयोजन को सांस्कृतिक रंग भी दिया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में साहसिक पर्यटन के प्रति रुचि विकसित करना, जिले में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना और अंदरूनी गांवों के बच्चों को नए अनुभव और आत्मविश्वास देना रहा। बड़ी संख्या में आदिवासी बच्चों की भागीदारी ने यह संदेश दिया कि अवसर मिलने पर वे भी किसी से कम नहीं हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जिला प्रशासन और कलेक्टर संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर मिश्रा ने खुद बच्चों के साथ जिपलाइन का आनंद लिया, जिससे बच्चों का उत्साह दोगुना हो गया। सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ गुमशुदा युवती को परिजन तक पहुंचाया

दंतेवाड़ा। जिले में पुलिस ने एक बार फिर यह साबित किया कि वर्दी के पीछे भी एक संवेदनशील दिल होता है। बचेली पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ और गुमशुदा युवती को सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की। 19 फरवरी को नियमित पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम को लेबर हाटमेंट क्षेत्र में एक युवती गंभीर हालत में मिली। युवती तेज बुखार से पीड़ित थी और मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रही थी।

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक इलाज कराया गया। युवती अपनी पहचान बताने की स्थिति में नहीं थी, जिससे उसकी जानकारी जुटाना चुनौतीपूर्ण हो गया। थाना प्रभारी प्रह्लाद कुमार साहू के निर्देश में पुलिस टीम ने युवती की पहचान के लिए व्यापक अभियान चलाया।

मजदूरी में नहीं जाने पर मजदूर का किया अपहरण

ठेकेदार समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

सक्ती। सक्ती जिले में मजदूर अपहरण मामले में ठेकेदार समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर मजदूर को जबरन कार में बिठा कर ले गया था। मजदूर की पत्नी ने पुलिस से घटना की शिकायत की थी।

मामला डभरा थाना क्षेत्र के ग्राम कांसा का है। जानकारी के अनुसार, ईंट भट्टे में काम करने के लिए मजदूर राकेश भारद्वाज को पैसा दिया गया था। इसके बाद काम पर नहीं जाने की वजह से ठेकेदार नरेश कुमार टंडन, शिव टंडन, देवानंद भारद्वाज, कीर्तन खांडे, परमेश्वरी टंडन मजदूर को जबरन उठा ले गए थे। आरोपी ठेकेदार अन्य प्रदेश के ईंट भट्टे में मजदूरों की सप्लाई करता है। पैसा लेने के बाद मजदूर के मजदूरी करने नहीं जाने के कारण विवाद हुआ। मामले में ठेकेदार और एक महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

मादा हाथी के सुरक्षित घेरे में विचरण करते दिखे नन्हें गजराज

रायगढ़। जिले के जंगल से हाथियों के दल का एक शानदार तस्वीर आई है। 11 हाथियों के दल बीच दो नन्हें शावक सुरक्षित घेरे में विचरण करते नजर आ रहे हैं, मामला धरमजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज का है। रायगढ़ जिले के जंगल से हाथियों के दल का ड्रोन कैमरे का एक शानदार तस्वीर सामने आई है। 11 हाथियों के दल में दो नन्हे शावक हैं जो अपनी मां के साथ जंगलों में घूमते नजर आ रहे हैं। हाथियों का यह दल छाल रेंज के कुडेकेला परिसर के गूडाघाट डेम किनारे विचरण कर रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मादा हाथी अपने शावक को सुरक्षित घेरे में रखते हुए जंगल में आगे बढ़ते नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों हाथी शावक की उम्र करीब 6 महीने के आसपास है। वन विभाग एवं हाथी मित्र दल की टीम ने कुडेकेला, बांसाझार के अलावा आस-पास गांव के ग्रामीणों को सावधानी बरतने के साथ-साथ किसी भी काम के सिलसिले जंगल तरफ नही जाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि हाथियों का यह दल अब घरघोड़ा रेंज में चला गया है।

कोरिया महोत्सव का भव्य समापन, लोक कला के बिखरे रंग

कोरिया। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में आयोजित तीन दिवसीय 'कोरिया महोत्सव' का गुरुवार देर रात भव्य समापन समारोह हुआ। कला, संस्कृति और परंपराओं से सजे इस महोत्सव ने पूरे जिले को उत्सवमय बना दिया। लोक रंग, शास्त्रीय संगीत, सूफियाना अंदाज़ और आधुनिक प्रस्तुतियों के समागम से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कोरिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को प्रदेश की पहचान और परंपराओं के संरक्षण के लिए आवश्यक बताया था। समापन दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत स्थानीय लोक कला दल की ओर से कर्मा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से हुई। पारंपरिक वेशभूषा और ढोल-मांदर की थाप पर प्रस्तुत इस नृत्य ने पूरे वातावरण को लोक रंग में रंग दिया। इसके बाद सियाधेश म्यूजिक और बॉलीवुड मिक्स की धुनों पर युवा देर रात तक झूमते नजर आए। बलविंदर सिंह ने सूफी गायन से श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया।

सोशल मीडिया में भड़काऊ बातें कहने वाला अरेस्ट

दुर्ग। जिले के भिलाई क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक भड़काऊ वीडियो को लेकर छावनी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो में आरोपी ने कथित रूप से हिंसक बातें कही थी। यही नहीं आरोपी ने पुराने मारपीट के वीडियो को एडिट कर उसमें जोड़ा था, जिससे सामाजिक तनाव फैलने की आशंका थी। शिकायत में उल्लेख किया है कि वीडियो में भगवा आतंकवाद जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए छावनी थाना पुलिस ने तुरंत वीडियो की जांच शुरू की। तकनीकी जांच और सत्यापन के बाद आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। सीएसपी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की भड़काऊ या भ्रामक सामग्री साझा करने से बचें।

सरगुजा में डॉग बाइट के चौंकाने वाले आंकड़े

सरगुजा। एक तरफ सरकार से लेकर अदालत स्ट्रीट डॉग्स के मामले को लेकर गंभीर है।वहीं दूसरी तरफ सरगुजा में इस गंभीरता पर ठीक ढंग से अमल नहीं हो रहा है।ये हम नहीं बल्कि वो आंकड़े बता रहे हैं,जिनमें डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। सरगुजा जिले में न सिर्फ आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा हुआ है बल्कि हर दिन करीब 12 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। ये स्थिति मानव जाति के लिए खतरनाक है। पशु प्रेम के कानूनों ने इंसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। डॉग बाइट और रेबीज को पशु एवं स्वास्थ्य विभाग ने समय पर उपचार न मिलने पर जानलेवा बताया है।फिर भी इस ओर सरगुजा में कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरगुजा जिले में बीते 5 साल के डॉग बाइट प्रकरणों पर नजर डाले तो साल दर साल ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए ना तो कुत्तों की नसबंदी की जा रही है और ना ही कोई अन्य उपाय होते नजर आ रहे है। आंकड़ो की बात करे तो वर्ष 2021 में 3345 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए।

डीएमएफ राशि को लेकर नारायणपुर में बवाल

नारायणपुर। जिले में संचालित रावघाट अंजरेल माइंस से मिलने वाली जिला खनिज न्यास राशि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर नारायणपुर के हिस्से की राशि कांकेर जिले को दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया। जिपं अध्यक्ष श्री मरकाम की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि रावघाट परियोजना का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा नारायणपुर जिले में स्थित है, और वर्तमान में खनन अंजरेल माइंस नारायणपुर क्षेत्र में ही चल रहा है, जबकि कांकेर वाले हिस्से में कोई खनन नहीं हो रहा। इसके बावजूद वर्ष 2021 से अब तक की डीएमएफ राशि कांकेर जिले को मातृत्व जिला मानकर दी जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। हमारे साथ छल किया गया। खनन के दुष्परिणाम से खराब सड़कें, प्रदूषण, भौगोलिक नुकसान, ग्रामीणों की स्वास्थ्य समस्याएं सब नारायणपुर के लोग झेल रहे हैं, लेकिन राशि किसी और जिले को दी जा रही ह।

उन्नति की ओर एक पहल कार्यक्रम, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ी लगी प्रदर्शनी

- जांजगीर चांपा जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है.जिसे उन्नति की ओर एक पहल नाम दिया गया है.

जांजगीर चांपा। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ 2026 की थीम पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में हो रहा है। इस कार्यक्रम को उन्नति की ओर एक पहल नाम दिया गया है। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के उपक्रमों और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं।केंद्र सरकार के अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए झींगा मछली पालन बहुत ही अच्छी योजना है। एक एकड़ में 20 से 21 लाख की कमाई की जा सकती है। जांजगीर चांपा जिला में युवा किसान और महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों और योजनाओं की जानकारी देने के लिए तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद कमलेश जांगड़े ने किया। वहीं भारत सरकार से आए कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी चेन्नई सेक्रेटरी के।सी। देवसेनापति ने भी प्रदर्शनी में हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए झींगा पालन की योजना शुरु की है। जिससे किसान एक साल मे 21 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं।उन्होंने छत्तीसगढ़ में डबरी और तालाब बहुत संख्या में होने के कारण अलग से ज्यादा कुछ नहीं करने का दावा किया। पहले से संचय जल में ही खेती किसानी से कई गुना ज्यादा आय अर्जित होने का दावा किया। इस कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कि हमारा देश और हमारा प्रदेश कृषि ही नहीं बल्कि आधुनिक हथियार, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ आवास, कृषि, बागवानी पशु पालन जैसे क्षेत्र में अग्रणी है।

पहले इस तरह की प्रदर्शनी बड़े बड़े शहरों में होती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार की योजना को जानने समझने के लिए जांजगीर और सक्ती जैसे जिला में प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इससे छात्र छात्राओं के साथ किसानों और सभी वर्ग को लाभ मिलेगा- कमलेश जांगड़े,सांसद

जांजगीर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित प्रदर्शनी में भारत सरकार की उपक्रमों के साथ-साथ राज्य सरकार की योजना का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे देखकर युवा महिला और किसान सभी खुश हैं। तीन दिनों तक इस प्रदर्शनी से जानकारी जुटाकर ग्रामीण भी केंद्र सरकार की योजना से जुड़कर लाभ लेने की तैयारी में है।

गृह मंत्री शर्मा ने पूर्व गृह मंत्री साहू के बयान पर किया प्रहार

- कहा- नक्सलियों के खिलाफ आज जब साय सरकार काम कर रही है तो कांग्रेस को उसमें भी राजनीति दिख रही है, धिक्कार है ऐसे लोगों को

कवर्धा। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्धारित समय सीमा के भीतर नक्सलियों को खत्म नहीं कर पाने वाले बयान पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पांच साल तक सरकार में रहने के दौरान अपने ही शहीदों के लिए कभी कुछ न कर पाए। और आज जब विष्णु देव साय की सरकार उस पर काम कर रही है, तो कांग्रेसियों को उसमें राजनीति दिखती है। धिक्कार है ऐसे लोगों को।छत्रपति शिवाजी की जयंती पर कवर्धा के शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी की भव्य प्रतिमा का उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर कहा कि जब भी मैं झीरम घाटी को क्रास किया हूं, शहीदों को याद किया हूं। कांग्रेस वाले भले ही कहते हैं कि हमारे लोग हैं। लेकिन हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व था। उन्होंने अपना कहा, लेकिन अपनी 5 साल की सरकार में उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। षड्यंत्र करते रहे। विजय शर्मा ने कहा कि आज भाजपा की सरकार देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया को रहा है, और उन शहीदों को हमारे सशत्र बल के जवान सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। झीरम में मैं रुककर उस स्थान को प्रणाम किया था, वहां एक मेमोरियल जैसा भी बना हुआ है। मैंने उसी दिन मन ही मन संकल्प लिया था कि जिस दिन नक्सलियों से प्रदेशवासियों को मुक्ति मिलेगी, उस दिन इन सारे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। परंतु कांग्रेस को इसमें में राजनीति दिखती है, तो धिक्कार है ऐसे पार्टी को।

संक्षिप्त समाचार

प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों को शासकीय विभागों में सीधी भर्ती में मिलेगा आरक्षण

रायपुर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम

2016 के प्रावधानों के तहत राज्य शासन के समस्त विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों की प्रत्येक सरकारी स्थापना में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन कर पद आरक्षित किए जा रहे हैं। आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिव शामिल हुए। बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के अंतर्गत सीधी भर्ती के प्रकम में भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में अंतिम रूप में पदों के चिन्हांकन हेतु विभागीय सचिवों से विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों के भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पदों के चिन्हाकन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी शामिल हुए।

दूषित पानी पीने से रविवि की एक दर्जन से अधिक छात्राओं को हुआ पीलिया

रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नवीन कन्या छात्रावास में दूषित पानी पीने से एक दर्जन से अधिक छात्राओं को पीलिया हो गया है।। इनमें से दो छात्राओं की हालत बिगडने पर उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। संक्रमण फैलने की आशंका से छात्रावास की कई छात्राएं घर लौट गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विज्ञान अध्ययन केंद्र की कई छात्राएं कुछ दिनों से उल्टी, कमजोरी और पीलिया जैसे लक्षणों से पीड़ित पाई गई। जांच के बाद संक्रमण की पुष्टि होने पर छात्राओं का उपचार शुरू किया। संक्रमण फैलने की आशंका से छात्रावास की कई छात्राएं घर लौट गई हैं। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में लंबे समय से पेयजल की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन नियमित सफाई और तकनीकी जांच नहीं कराई गई। वाटर कूलरों की समय पर सफाई और पानी की जांच नहीं होने से संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। छात्राओं का कहना है कि पानी में बदबू और रंग बदलने की शिकायतें पहले भी सामने आई थीं, लेकिन प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

चाकू लेकर आम लोगों को डराने वाला रोनित पंडित गिरफ्तार

रायपुर। सिंघानिया चौक के पास अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को डराते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी रोनित पंडित निवासी बजरंग नगर तुलसी चाईस सेंटर बीरगांव को उरला पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 नग धारदार चाकू जप्त किया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 52/26 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।

रौचन जलाशय और रानो स्टापडेम रपटा निर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा दो सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 7 करोड़ 12 लाख 63 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत कार्यों में कबीरधाम जिले के विकासखण्ड-बोड़ला की रौचन जलाशय योजना के शीर्ष कार्य, नहरों के जीर्णोद्वार और लाईनिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 72 लाख 82 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने पर रूपांकित सिंचाई क्षमता 346.55 हेक्टेयर के विरूद्ध 160 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 32 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 378.55 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। दुर्ग जिले के विकासखण्ड-साजा की रानो स्टापडेम कम रपटा निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 39 लाख 81 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के निर्माण से निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन के साथ ही किसानों द्वारा स्वयं के साधन से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जल संसाधन मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

राज्यपाल डेका ने किए महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने शुक्रवार

को रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन एवं पूजन कर देश एवं प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।

राज्य सरकार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध : साय

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों और नवाचारों की सराहना की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की संयुक्त अध्यक्षता में शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश में जल संचय-जन भागीदारी 2.0 अभियान के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए और बैठक को संबोधित किया। इस दौरान बिलासपुर, दुर्ग और सूरजपुर जिले के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल संकट 21वीं सदी की केवल गंभीर पर्यावरणीय ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए जनभागीदारी अनिवार्य है।उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का उल्लेख किया, जिसमें पानी के उपयोग को प्रसाद के समान मानते हुए जल के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर राज्य सरकार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभियान के पहले चरण में छत्तीसगढ़ ने देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा विभिन्न जिलों को भी अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले। पहले चरण में सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पर कार्य करते हुए बड़े पैमाने पर बोरवेल रिचार्ज, रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज शाफ्ट, सोक पिट और ओपनवेल रिचार्ज जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 5 क्रिटिकल और 21 सेमी-क्रिटिकल भू-जल ब्लॉक चिन्हित हैं। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में इनमें से 5 ब्लॉकों में भू-जल निकासी में कमी और भू-जल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है, जो जल संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणामों का संकेत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण जल संचय-जन भागीदारी 2.0 के अंतर्गत तकनीक आधारित और अधिक परिणाममूलक रणनीति अपनाई जा रही है। राज्य सरकार ने 31 मई 2026 तक 10 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने इसे जल सुरक्षा की दिशा में प्रदेश का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक विशेष पहल के तहत 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले चार लाख से अधिक किसानों को अपने खेतों में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्य में जिला प्रशासन के साथ-साथ औद्योगिक समूहों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इन डबरियों से भू-जल स्तर में वृद्धि के साथ किसानों को सिंचाई एवं मछली पालन जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में सभी जल संरचनाओं की जियोटैगिंग, ग्राम पंचायतों के वॉटर बजट तथा जल सुरक्षा योजनाओं के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही गांवों के युवाओं को जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि अभियान को गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि क्रिटिकल और सेमी-क्रिटिकल ब्लॉकों पर विशेष फोकस रखते हुए सेमी-क्रिटिकल ब्लॉकों में 40 प्रतिशत तथा क्रिटिकल ब्लॉकों में 65 प्रतिशत जल संरक्षण कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने, जल संरचनाओं की रक्षा करने और जल के प्रति जिम्मेदार सोच अपनाने का आह्वान भी किया।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों और नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जल संरक्षण के प्रयासों में छत्तीसगढ़ देशभर में दूसरे स्थान पर रहा, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 को सूरत से 'जल संचय जन भागीदारी अभियान' की शुरुआत की थी और 'कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए जल संचयन में सहयोग' का आह्वान किया था। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को जनआंदोलन का रूप देना है।

केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों से मनरेगा के तहत जल संचय कार्यों के लिए प्राप्त राशि का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने राजनांदगांव प्रवास के दौरान एक महिला सरपंच द्वारा स्वयं के प्रयासों से जल संचयन के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने जल संचय में व्यापक जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो तथा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री कांताराव और छत्तीसगढ़ के समस्त कलेक्टर वर्चुअली उपस्थित थे।

मार्च में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे

■ छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने दी जानकारी

रायपुर। कांग्रेस शासनकाल में हुए फरवरी 2023 को हुए कांग्रेस महाधिवेशन में एक साथ छत्तीसगढ़ में मंच साझा करने के बाद अब फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ-साथ आने के आसार बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि मार्च के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित रैली में दोनों नेता शामिल हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पिछले दो साल में भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया है। चार बार बिजली की दर बढ़ाई गई। अब विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई चल रही है, इसका

मतलब साफ है कि सरकार बिजली बिल बढ़ाना चाहती है। साथ ही केंद्र ने सेस भी कम कर दिया।

वहीं राज्यसभा की छत्तीसगढ़ सीट को लेकर दीपक बैज ने कहा कि राज्यसभा में कौन जाएगा यह पार्टी तय करेगी। बस्तर से सरगुजा तक कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। पार्टी का अधिकार है किसे नॉमिनेट करना है, अगर हमसे सलाह मांगेंगे तो जरूर देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फ्रीबीज को लेकर की गई टिप्पणी पर बैज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत है। बिहार में चुनाव के समय 10 हजार बांटे गए, असम में भी 10 हजार बांटे जा रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए।

विष्णु सरकार के द्वारा आगामी 24 फ़रवरी को पेश किए जाने वाले बजट को लेकर कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस विधायक दल द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश होगी। विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं स्क्रुकी फाइनल लिस्ट जारी होने के मामले में दीपक बैज ने कहा कि बहुत गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता नियमों को ताक पर रख रहे हैं। अब आगे देखना है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि छत्तीसगढ़ समेत ओडिशा और झारखंड के 100 से अधिक जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में हो सकता है। प्रशिक्षण के लिए जगह की तलाश की जा रही है। 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में तीनों राज्यों के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे।

भ्रामक विज्ञापन पर सीजी रेरा की कड़ी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में सख्त कदम उठाते हुए बिलासपुर के बोदरी स्थित 'फॉर्च्यून एलिमेंट्स' परियोजना के प्रवर्तक श्री पवन अग्रवाल पर 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है। उक्त परियोजना का पंजीयन एक प्लॉटेड परियोजना के रूप में किया गया है। किंतु प्राधिकरण द्वारा विभिन्न माध्यमों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रमोटर द्वारा परियोजना का प्रचार हाउसिंग परियोजना के रूप में किया जा रहा था, जो कि पंजीकृत विवरण के विपरीत एवं भ्रामक है। रेरा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि कोई प्रवर्तक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा परियोजना से संबंधित गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकरण परियोजना के पंजीयन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, जिसमें पंजीयन निरस्तीकरण सहित अन्य दंडात्मक कदम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रवर्तक के लिए यह अनिवार्य है कि वह परियोजना का विकास एवं प्रचार स्वीकृत योजना, ले-आउट, विनिर्देश तथा पंजीयन के समय दी गई जानकारी के अनुरूप ही करे।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता एवं सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के कुल 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। शासन ने परीक्षा आयोजन के लिये छत्तीसगढ़ व्यापम को अधिकृत किया है एवं विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आवश्यक प्रपत्र व्यापम को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही सीधी भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया फरवरी 2026 में शुरू करने जा रही है। इन पदों के लिए चयन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, यह भर्ती राज्य के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए की जा रही है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस आने वाले दिनों में जारी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। खास बात यह है कि इसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक जैसे कई पद शामिल किए जा रहे हैं, जिससे अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा।

ज्ञातव्य है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद के पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारियों के स्थापन पर डी.एड. अर्हताधारियों अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया है।

वाणिज्य कर विभाग में 9 अधिकारियों व कर्मचारियों का हुआ तबादला

रायपुर। राज्य सरकार ने वाणिज्यकर कर विभाग में 9 अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। सूची में आयुक्त स्तर से लेकर उपायुक्त, सहायक आयुक्त तथा राज्य कर अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग जिलों और संभागों में पदस्थ किया गया है। जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जारी आदेश के मुताबिक अजय देवांगन, राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, जगदलपुर संभाग से कार्यालय राज्य कर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर, सुमित कुमार महोबिया, राज्य कर उपायुक्त राज्य कर, बी.आई.यू., बिलासपुर से कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर, श्रीमती शारदा मिश्रा, राज्य कर सहायक आयुक्त, सचिव, छ.ग. वाणिज्यिक कर अधिकरण, नवा रायपुर से ऑडिट, रायपुर संभाग-दो, आनंद कुमार डोंगरे, राज्य कर सहायक आयुक्त कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त रायपुर वृत्त-8 से कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरिया वृत्त मर्नेन्द्रगढ़, सुरेन्द्र कुमार पटेल, राज्य कर सहायक आयुक्त कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरिया वृत्त मनेन्द्रगढ़ से कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बेमेतरा वृत्त, श्रीमती चित्ररेखा भूआर्य, राज्य कर अधिकारी कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त रायपुर वृत्त-11 से कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-03, श्रीमती अंशु शुक्ला, राज्य कर अधिकारी कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त बिलासपुर वृत्त-03 से कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर सरगुजा संभाग अंबिकापुर, श्रीमती सुनीता सोनी, राज्य कर अधिकारी कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त भाटापारा वृत्त से कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त रायपुर वृत्त 2 तथा आशीष कुमार साहू राज्य कर निरीक्षक बी.आई.यू. दुर्ग संभाग से कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त दुर्ग वृत्त 2 में नवीन पदस्थापना की गई है।

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विवि को नया नेतृत्व

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति रामेन डेका ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के लिए नए कुलपति की नियुक्ति की घोषणा की है। इस पद के लिए प्रोफेसर मनोज दयाल को चयनित किया गया है। वे वर्तमान में गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार (हरियाणा) के मास कम्युनिकेशन विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।

जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 तथा संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

रानी रोड कोरबा से सर्वमंगला मंदिर के बीच हसदेव नदी पर बनेगा रपटा

■ उद्योग मंत्री की प्रयासों से मिली 13.44 करोड़ की स्वीकृति

रायपुर। कोरबा नगर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के विशेष प्रयासों से कोरबा शहर के विकास को नई दिशा मिल रही है। इसी कड़ी में रानी रोड कोरबा से सर्वमंगला मंदिर के बीच हसदेव नदी पर रपटा निर्माण हेतु 13.44 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शासन से मिली है।

उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पुरानी कोरबा शहर की वर्षों पुरानी मांग थी कि रानी रोड से सर्वमंगला मंदिर के बीच एक रपटा का निर्माण हो जाए, ताकि सर्वमंगला मंदिर एवं कुसमुंडा या फिर कनकी बिलासपुर की ओर जाने के लिए उषा कॉम्प्लेक्स रेलवे क्रॉसिंग से सर्वमंगला पुल से घूम कर जाना ना पड़े। पुराने शहर के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवकों एवं जनों द्वारा इसके लिए लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। इस जन आकांक्षाओं को प्राथमिकता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कोरबा आगमन पर उनसे विशेष आग्रह किया गया था, मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। तत्पश्चात सेतु निगम के माध्यम से रपटा निर्माण हेतु

ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया। इस महत्वपूर्ण निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा 13.44 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। जल्दी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। इसके पूर्ण होने से सर्वमंगला पुल पर एक तरफ जहां यातायात दबाव कम होगा, वहीं क्षेत्र को विकास और समृद्धि की नई राह मिलेगी। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति हेतु कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का आभार जताया।

पर्यटन मंत्री ने हैमर थ्रो में राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुधा सिंह को किया सम्मानित

रायपुर। शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर, केवरा की बीएससी की प्रतिभावान छात्रा सुधा सिंह ने एथलेटिक्स की हैमर थ्रो विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि से महाविद्यालय परिवार सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का वातावरण है।

इस उल्लेखनीय सफलता पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने छात्रा सुधा सिंह को सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण अंचलों की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। आवश्यकता केवल उन्हें उचित मंच, संसाधन और प्रोत्साहन देने की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अवसरों का विस्तार कर रही है, ताकि प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। सुधा सिंह की उपलब्धि यह सिद्ध करती है कि लगन, परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं।

मंत्री श्री अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि हमारा संकल्प है कि बेटियों की प्रतिभा को उचित मंच और अवसर मिले, उनके सपने साकार हों। सुधा सिंह जैसी प्रतिभाएं न केवल अपने परिवार और महाविद्यालय का, बल्कि पूरे क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करती हैं।

महाविद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने भी छात्रा की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने भी सुधा सिंह को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सुधा सिंह की इस सफलता ने यह संदेश दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी मुकाम दूर नहीं। खेल के क्षेत्र में उनकी यह उपलब्धि आने वाले समय में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होने का संकेत है।

खेल आपसी सद्भाव, अनुशासन और टीम भावना को मजबूत करने का सशक्त माध्यम:राजस्व मंत्री

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब खेल मड़ई 2026 के अंतर्गत आयोजित स्व. कुलदीप निगम स्मृति इंटर प्रेस क्रिकेट स्पर्धा का खिताब इलेक्ट्रॉनिक संयुक्त इलेवन ने अपने नाम कर लिया। समापन समारोह में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि आपसी सद्भाव, अनुशासन और टीम भावना को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और जब वे खेल के मैदान में उतरते हैं तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश समाज तक पहुंचता है। उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजन निरंतर कराने की अपेक्षा जताई। नेताजी सुभाष स्टेडियम में खेले गए फाइनल में विस्तार न्यूज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 60 रन बनाए। जवाब में संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक इलेवन ने 7.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। हेमंत डोंगरे (14 रन), तिलक साहू (12 रन) और लक्ष्मण लेखवानी (17 रन) की पारियों ने टीम को जीत दिलाई। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए हेमंत डोंगरे को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल के लिए संजय सिंहदेव को प्लेयर ऑफ द सीरीज सम्मान मिला। विजेता टीम के कप्तान मोहन तिवारी ने ट्रॉफी के साथ 51,000 रुपये का प्रतीकात्मक चेक और स्वर्ण पदक ग्रहण किए। उपविजेता टीम को 41,000 रुपये का चेक एवं रजत पदक प्रदान किए गए। सेमीफाइनल में उपविजेता रही एस. जरनो और IBC 24 की टीमों को 21,000-21,000 रुपये के प्रतीकात्मक चेक एवं कांस्य पदक दिए गए।

एआई की वैश्विक दुनिया में छाप छोड़ता भारत

अभिषेक कुमार सिंह

कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- एआई) इस समय दुनिया की चिंताओं में शामिल होने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हीं चिंताओं के बीच भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ है, जिसमें तमाम शीर्ष नेता, नीति-निर्माता, अरबपति कारोबारी, इंजीनियर, तकनीशियन हिस्सा ले रहे हैं। तकनीक की दुनिया में एआई का आगमन एक क्रांतिकारी परिवर्तन की तरह हुआ है। लंबे समय तक छिटपुट प्रयासों के बाद करीब साढ़े तीन साल पहले नवंबर 2022 में चैटजीपीटी के लॉन्च के साथ इस तकनीक ने इंसानी संवादों की भाषा समझने और निर्देशों का पालन करते हुए समस्याएं सुलझाने और कंटेंट बनाने की जो अभूतपूर्व क्षमता दिखाई, वह आज इस मोड़ पर आ गई है कि हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। इसकी सहूलियतों के बाहर हालांकि अभी इसकी समस्याओं को लेकर दुविधाओं-जटिलताओं की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह की हलचल विश्व स्तर पर इस तकनीक ने पैदा की है, उसी का परिणाम है कि भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मंच पर दुनिया भर के विशेषज्ञ और नीति-निर्माता एक साथ जुट गए। जहां तक भारत की बात है, तो यह देश पहले से आईटी क्षेत्र में मजबूत है। ऐसे में स्वाभाविक है कि देश में एआई को एक नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इसी दृष्टिकोण से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया एआई मिशन के तहत आयोजित इस समिट में 140 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। 'जिम्मेदार बुद्धिमत्ता' की थीम पर आधारित इस आयोजन को सिर्फ तकनीकी चर्चा का मंच कहना पर्याप्त नहीं होगा। बल्कि एआई के वास्तविक उद्देश्य, उस पर नियंत्रण और विकास पर वैश्विक विमर्श के कई पहलुओं पर एक स्पष्ट नजरिया हासिल करने का यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब एआई स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है। वैश्विक स्तर पर एआई अपनाने की होड़ तेज है जिसमें अमेरिका, चीन, भारत और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। भविष्य में सफलता नीतियों, निवेश, युवा प्रशिक्षण और नवाचार पर निर्भर करेगी। इस समिट का उद्देश्य भारत को एआई में अग्रणी बनाना और युवाओं को बड़े पैमाने पर इसके लिए तैयार करना है। साथ ही ऐसे वैश्विक नियमों की जरूरत है, जो विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। एआई मानवता की सेवा करे, इसके लिए एआई समिट जैसे संवाद जरूरी हैं। असल प्रश्न यह है कि क्या यह समिट भारत के लिए केवल एक आयोजन भर है या यह उस बड़े परिवर्तन का संकेत है, जिसमें भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक भविष्य को आकार देने वाला प्रमुख देश बन सकता है। आज जब दुनिया तेजी से डिजिटल और स्वचालित प्रणालियों की ओर बढ़ रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उस परिवर्तन का केंद्रीय तत्व बन चुकी है। यह केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक विकास, रोजगार संरचना और सामाजिक व्यवस्था को पुनर्परिभाषित करने वाली तकनीक बन गई है। ऐसे समय में भारत द्वारा इस तरह के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करना इस बात का संकेत है कि देश केवल तकनीक का उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह इसके निर्माता, नियंत्रक और नीति-निर्धारक के रूप में भी अपनी भूमिका स्थापित करना चाहता है। वैसे तो यूरोप में ऐसे कुछ आयोजन पहले भी हो चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब किसी विकासशील राष्ट्र में इतने बड़े स्तर पर एआई समिट का आयोजन हुआ है।

बांग्लादेश और चुनावी सियासत

अजय बोकिल

चुनाव हारने के बाद 'जनादेश चोरी' अथवा 'वोट चोरी' का इल्जाम लगाना अब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति बनती जा रही है। पहले इस तरह के आरोप अमूमन हारने वाली सियासी पार्टियां चुनाव में धांधली अथवा नतीजों में हेराफेरी के रूप में लगाती थीं और ये आरोप अक्सर उस पार्टी पर लगते थे, जो चुनाव के समय सत्ता में रहती थी। भारत में भी राहुल गांधी और कुछ विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ भाजपा और मोदी सरकार पर 'वोट चोरी' और 'जनादेश चुराने' के आरोप लगातार लगाते रहे हैं।

अब बांग्लादेश में भी इसकी अनगूंज सुनाई दे रही है। वहां चुनाव में मात खाने वाली जमात-ए-इस्लामी और 11 पार्टियों के गठबंधन ने सत्ता में आई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) पर 'जनादेश चुराने' और वोटों की गिनती में 'हेराफेरी' का आरोप लगाया है। नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सोशल मीडिया में ट्रोलकर उन्हें चुनाव जितवाने वाला 'इंजीनियर' बताया जा रहा है। हार की हताशा में ऐसा ही आरोप छह साल पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाया था, जब राष्ट्रपति पद का दूसरा चुनाव वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों हार गए थे।

दरअसल, इस बात की पड़ताल दिलचस्प है कि ऐसे आरोप महज हार की बौखलाहट में लगाए जाते हैं? अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगाए जाते हैं अथवा इनमें सच में बहुत दम होता है? खासकर तब, जब जीत- हार तगड़े मार्जिन के साथ हुई हो? या फिर ऐसे आरोपों का वास्तविक मकसद जनादेश को नकारकर उसका अपमान करना है? ऐसा लगता है कि देश कोई-सा भी हो, अगर लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होने हैं तो किसी न किसी की हार या जीत तो होगी ही। यानी जनता जो आदेश देगी, वही वैध और शिरोधार्य होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जनादेश की पवित्रता पर संदेह का दाग लगाने की संस्कृति तेजी से फली-फूली है। इसमें आंशिक सच्चाई भी है।

बांग्लादेश के ताजा आम चुनाव वहां की मोहम्मद युनूस अंतरिम सरकार की देखरेख और प्रशासन की निगरानी में हुए थे। बीएनपी तो सत्ता से बाहर ही थी। बल्कि युनूस सरकार परोक्ष रूप से मुस्लिम कट्टरपंथी जमात- ए- इस्लामी और

जेन-जी की नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के दबाव में काम कर रही थी। कोशिश थी कि बांग्लादेश को उदार इस्लामिक स्टेट से कट्टरपंथी इस्लामिक देश में तब्दील कर कड़े शरिया कानून लागू किए जाएं। यानी देश में बंगाली अस्मिता की जगह मुस्लिम पहचान को तरजीह दी जाए। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने इस चाल को साफ नकार दिया, जिसमें वहां की महिलाओं की विशेष भूमिका रही, जो बुर्के में जिंदगी गुजारने के लिए कतई तैयार नहीं थी। जमात इस भावना को समझना नहीं चाहती थी। नतीजा यह हुआ कि अपेक्षाकृत मध्यमार्गी बीएनपी को चुनाव में बंपर जीत मिली।

उसने 299 में 209 सीटें और 49.97 फीसदी यानी आधे वोट हासिल किए, जबकि कट्टर इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और 11 पार्टियों के गठबंधन को 68 सीटें और 31.76 प्रतिशत वोट ही मिले। शेख हसीना की सरकार को हटाकर 'नया बांग्लादेश' बनाने का दावा करने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी को महज 6 सीटें और 3 फीसदी वोट ही मिले। उसके ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव हार गए।

इस तगडी हार के बाद जमात और एनसीपी आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। यानी माहौल तो हमारे पक्ष में था, लेकिन नतीजे विपरीत आए। मतदान ठीक हुआ, लेकिन मतगणना में हेराफेरी हुई।

हमारे कई प्रत्याशियों को मामूली अंतर से हरवा दिया गया इत्यादि। ये सभी आरोप भारत में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव नतीजों के बाद मोदी सरकार और भाजपा पर लगाए जाने वाले आरोपों की फोटो कॉपी लगते हैं। यहां एक फर्क और है।

बांग्लादेश में मतदान बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि भारत में ईवीएम से चुनाव होता है। कांग्रेस और विपक्ष यह आशंका बार-बार जाहिर करते रहे हैं कि चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी कराती है और चुनाव जीत जाती है। लेकिन बांग्लादेश का उदाहरण बताता है कि अगर जमात और अन्य पार्टियों के आरोप सही हैं तो बैलेट पेपर में धांधली तो और भी आसान है।

यह हमने पाकिस्तान के आम चुनाव में देखा, जहां बैलेट पेपर के जरिए हुए मतदान में वहां की सेना ने खुलेआम धांधली की और शहबाज शरीफ को जितवा दिया। अमेरिका में बैलेट पेपर और मशीन दोनो के जरिए चुनाव होता है, फिर भी ट्रंप सत्ता में रहकर भी पिछला चुनाव हार गए थे।

भारत में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां 'वोट चोरी' का आरोप अमूमन उन राज्यों में लगाती है, जहां भाजपा सत्ता में है। लेकिन बांग्लादेश में तो चुनाव जीती बीएनपी सत्ता से बरसों से बाहर थी, फिर वो इतने बड़े पैमाने पर 'गड़बड़ी' करने में कैसे कामयाब हो गई? और जमात जैसी पार्टियां, जिनका कि सत्ता पर परोक्ष नियंत्रण था, इस 'गड़बड़ी' को क्यों नहीं रोक पाई? उसका यह दावा कि चुनाव के समय माहौल उनके 'पक्ष' में था तो मतदान के वक्त अरब सागर की हवा कैसे बदल गई?

हाल में भारत के राज्य तेलंगाना में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव हुए हैं। इसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस को बंपर जीत मिली है। लेकिन ये चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए गए।

इन नतीजों से कांग्रेस 'संतुष्ट' है, क्योंकि उसे जीत मिली है, जबकि चुनाव नतीजों पर विपक्षी भाजपा ने सवाल उठाया अब कोई 'जनादेश चुराने' का आरोप क्यों नहीं लगा रा है? इसका सीधा मतलब है कि यदि नतीजा अपने पक्ष में आए तो सब ठीक और न आए तो 'आंगन टेढ़ा।'

अब सवाल यह है कि भारत में ईवीएम से जहां चुनाव होते हैं, वहां कांग्रेस अमूमन हार जाती है और जहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो जीत जाती है? यह मतदान के माध्यम और तरीके का नतीजा है अथवा जनमत की अभिव्यक्ति?

अगर ईवीएम से ही हार-जीत तय होती तो भाजपा को दक्षिणी राज्यों और बंगाल में भी भारी बहुमत से जीतना चाहिए था। क्योंकि विपक्ष के अनुसार उसके पास तो चुनाव आयोग का रिमोट कंट्रोल भी है। और अगर बैलेट पेपर से ही हार-जीत का उचित फैसला होता हो तो बांग्लादेश में जमात और एनसीपी को बंपर जीत मिलनी चाहिए थी।

कहने का आशय यह कि जब राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर अपना असर नहीं छोड़ पातीं, लोगों से जुड़ने का कैडर उनके पास नहीं होता, चुनाव जीतने की जिद नहीं होती, जनमानस से पार्टियों की सोच का तालमेल नहीं बैठता या फिर वे केवल हवा में लठ घुमा कर और शाब्दिक क्रांति से ही चुनाव जीतना चाहती हैं तो यह केवल खुद को धोखे में रखना है।

चुनाव जीतने के लिए सत्ता और धन के दुरूपयोग के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जनता की नब्ज को पकड़ना है। बांग्लादेश में भी जमात द्वारा लगाया जा रहा 'जनादेश चोरी' का आरोप तब सही माना जा सकता था, जब दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के बीच हार-जीत का फैसला मामूली अंतर से होता। अब कोई जनता की सोच और समझ पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना चाहे तो लोकतंत्र में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

सो यहाँ वेद में जिस सोम को सुवर्ण का अन्यतम उत्पादक प्रकट किया है वहीं इस आख्यान में पुराण का श्रभिमत शिव किंवा महादेव है। संस्कृत के सभी कोशोंमें उमया सहित: इस अर्थ में सोम शिव का ही अन्यतम नाम स्वीकार किया गया है। चन्द्रमा रात्रिचर भूनों का अधिपति है, कपूर के समान गौरवर्ण है, हिमांशु होनेके नाते हिमालय का अधिष्ठाता है, यही सब विशेषण हमारे शिव जी के साथ भी तथैव सबद्ध हैं। उसे कोई-भूतेशो भूतभावन: कोई कर्पूरगौरं करुणावतारं श्रीर कोई-हर: शेते हिमगिरी कहकर याद करते हैं! वेद में जिस शक्ति को अग्नि नाम से प्रकट किया है वही इस ग्राख्यायिका में श्रीमद्भागवत पुराण का अभिमत विष्णु है। अग्नि देदीप्यमान भास्वर-शुक्ल-स्वरूप-सम्पन्न एवं श्रग्नियेर्थको भुवनं प्रविष्ट: के अनुसार व्यापनशील तत्त्व है, विष्णु भी व्यापकत्वधर्मावच्छिन्न शवित को ही कहते हैं, तथा उसे भी शुक्लाम्बर-घरं विष्णु शशिवर्णम् आदि प्रार्थनाओं में भास्वर-शुक्ल-स्वरूप वाला कहा जाता है ।

यदि हम उक्त ग्राख्यायिका को वैज्ञानिक शब्दों में प्रकट करना चाहें, तो इस प्रकार कह सकते हैं- आदि सृष्टि रचना के समय जब कि ब्रह्माण्ड में प्राणियों का उद्भव न हो पाया था और हमारी इस पृथ्वी की भी कोई सत्ता बिद्यमान न थी, उस समय केवल आग्नेय वाष्प ही सर्वत्र फैला हुआ था, समय पाकर वह आग्नेय वाष्प क्रमश: घनीभूत होने लगा और एक मुद्दत के बाद वह हमारी इस पृथ्वी का आदिमपिण्ड बन गया। कहना न होगा कि आग्नेय वाष्प के घनीभूत होने में चन्द्रपिण्ड का पूरा सहयोग था अर्थात् चन्द्रमा की स्वाभाविक शीतलता के संयोग से ही निकटवर्ती आग्नेय वाष्प घनत्व को प्राप्त हुई थी। श्रीवेदव्यास जी महाराज ने इसी गम्भीर तत्त्व को सरल बनाने के लिये रूपक शैली का आश्रय लिया है।

क्रमशः ...

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

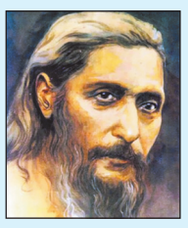

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फ़रवरी 1896 को बंगाल की महिषादल रियासत (ज़िला मेदिनीपुर) में हुआ। इस जन्मतिथि को लेकर अनेक मत हैं, लेकिन इस पर विद्वतजन एकमत हैं कि 1930 से निराला वसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाया करते थे। 'महाप्राण' नाम से विख्यात निराला छायावादी दौर के चार स्तंभों में से एक हैं। उनकी कीर्ति का आधार 'सरोज-स्मृति', 'राम की शक्ति-पूजा' और 'कुकुरमुत्ता' सरीखी लंबी कविताएँ हैं; जो उनके प्रसिद्ध गीतों और प्रयोगशील कवि-कर्म के साथ-साथ रची जाती रहीं। उन्होंने पर्याप्त कथा और कथेतर-लेखन भी किया। बतौर अनुवादक भी वह सक्रिय रहे। वह हिंदी में मुक्तछंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वह मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति के पक्षधर हैं। वर्ष 1930 में प्रकाशित अपने कविता-संग्रह 'परिमल' की भूमिका में उन्होंने लिखा : ''मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है।''

निराला के बचपन में उनका नाम सुर्जकुमार रखा गया। उनके पिता पंडित रामसहाय तिवारी उन्नाव (बैसवाड़ा) ज़िले गढ़ाकोला गाँव के रहने वाले थे। वह महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा और साहित्य का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से अर्जित किया। उनका जीवन उनके ही शब्दों में कहें तो दु:ख की कथा-सा है। तीन वर्ष की आयु में उनकी माँ का और बीस वर्ष के होते-होते उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद की उनकी जीवन-स्थिति को उनकी काव्य-पंक्तियों से समझा जा सकता है-

''धन्ये, मैं पिता निरर्थक का,
कुछ भी तेरे हित न कर सका!
जाना तो अर्थागमोपाय,
पर रहा सदा संकुचित-काय
लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर
हारता रहा मैं स्वार्थ-समर।''

ये पंक्तियाँ निराला की कालजयी कविता 'सरोज-स्मृति' से हैं। यह कविता उन्होंने मात्र उन्नीस वर्ष आयु में मृत्यु को प्राप्त हुई अपनी बेटी सरोज की स्मृति में लिखी। निराला का व्यक्तित्व घनघोर सिद्धांतवादी और साहसी था। वह सतत संघर्ष-पथ के पथिक थे। यह रास्ता उन्हें विक्षिप्तता तक भी ले गया। उन्होंने जीवन और रचना अनेक संस्तरों पर जिया, इसका ही निष्कर्ष है कि उनका रचना-संसार इतनी विविधता और समृद्धता लिए हुए है। हिंदी साहित्य संसार में उनके आक्रोश और विद्रोह, उनकी करुणा और प्रतिबद्धता की कई मिसालें और कहानियाँ प्रचलित हैं। उनके जीवन का उत्तरार्द्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज नाम के मुहल्ले में 15 अक्टूबर 1961 को उनका देहावसान हुआ।

'अनामिका' (1923), 'परिमल' (1930), 'गीतिका' (1936), 'तुलसीदास' (1939), 'कुकुरमुत्ता' (1942), 'अणिमा' (1943), 'बेला' (1946), 'नए पत्ते' (1946), 'अर्चना' (1950), 'आराधना' (1953), 'गीत कुंज' (1954), 'सांध्य काकली' और 'अपरा' निराला की प्रमुख काव्य-कृतियाँ हैं।

अमेरिका-भारत में संविधान और लोकतंत्र के नये मानक?

सनत जैन

विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका और भारत आज केवल राजनीतिक एवं व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को नये तरीके से परिभाषित करने के केंद्र बन रहे हैं। इस कारण अमेरिका और भारत की संघीय लोकतांत्रिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में तकनीकी क्रांति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक विविधताओं के बीच इन दोनों देशों ने संविधान और लोकतंत्र की नई व्याख्या करने की शुरुआत कर दी है, जो शासक आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं जवाबदेही तय होती है। भारत में पिछले कई वर्षों से सत्ता का केंद्रीकरण होता जा रहा है।

अमेरिका में भी दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, उससे भी शासन व्यवस्था में ट्रम्प का एकाधिकार अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के जो राज्य हैं, उनकी दूरी केंद्रीय सत्ता से बढ़ती चली जा रही है। नई व्याख्या परंपरागत मूल्यों को बनाए रखते हुए समयानुकूल बदलाव के लिए लोकतांत्रिक पद्धति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्व की तरह बना रहेगा, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी। भारत का संविधान विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं की असंख्य धाराएँ संविधान एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाहित हैं। वहीं अमेरिका का संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानव अधिकारों की रक्षा एवं संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। दोनों देशों ने अपने-अपने ऐतिहासिक अनुभवों से लोकतंत्र को मजबूत किया था।

अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम और नागरिक अधिकार आंदोलनों से, वहीं भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक न्याय के लिए भारतीय संविधान तैयार किया था। भारतीय संविधान ने

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और न्यायिक तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर कई चुनौतियों का सामना अमेरिका और भारत दोनों को ही करना पड़ रहा है। चाहे वह, सत्ता के केंद्रीयकरण का मामला हो या फेक न्यूज़ का प्रसार हो। वैधानिक संस्थाओं पर सत्ता का बढ़ता दबाव लोकतंत्र और न्याय तंत्र दोनों को ही प्रभावित कर रहा है। मानव अधिकारों को लेकर वह स्वतंत्रता अब नहीं मिलती, जैसे कुछ समय पहले देखने को मिलती थी। ऐसे समय में भारत और अमेरिका में सत्ता पक्ष द्वारा लोकतंत्र को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। यह परिभाषा केवल चुनावी प्रक्रिया और सत्ता तक सीमित नहीं है।

अमेरिका और भारत में शासन व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटल अधिकारों और नागरिक अधिकारों को लेकर तनाव के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका मे जो निर्णय ले रहे हैं, उनमें वे अमेरिकन कानूनो को नजर अंदाज कर रहे हैं। राज्य और केंद्र के बीच में भी मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं। यही स्थिति भारत में भी देखने को मिल रही है। डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन एक बड़ी चुनौती है। भारत और अमेरिका दोनों ने तकनीकी कंपनियों के नियमन, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ट्रेड डील के माध्यम से नई पहल की है। इससे स्पष्ट है, वैश्विक व्यापार संधि के बाद जिस तरह के वैश्विक नियम और कानून बनाए गए थे उनसे हटकर अमेरिका अपने व्यापारिक समझौते करना चाहता है।

भारत एवं अन्य देशों पर अमेरिका जो दबाव बना रहा है, उसके कारण वैश्विक स्तर पर अभी तक जो डॉलर की स्वीकार्यता थी, वैश्विक व्यापार में अमेरिका और डॉलर का जो वर्चस्व था, अब उसे चुनौती मिलना शुरू हो गई है। जिसके कारण संपूर्ण दुनिया के देशों में लोकतंत्र और तानाशाही व्यवस्था को लेकर चर्चा होने लगी है। लोकतंत्र अब केवल संसद, सरकार, कार्यपालिका और न्यायालय तक सीमित नहीं रहा। संविधान की भावना मानव अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिजिटल तकनीकि के साथ जवाबदेही तय करना समय की मांग बन चुकी है।

वर्तमान संदर्भ में सामाजिक न्याय और समान अवसर को लेकर लोकतंत्र की नई परिभाषा में बदलाव की जरूरत है। अमेरिका में नस्लीय समानता और भारत में सामाजिक भाषा एवं धार्मिक समावेश में संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार में सभी को समान अवसर और गरिमा सुनिश्चित करने कुछ बदलाव जरूरी हैं। पिछले कुछ वर्षों से सत्ता पाने के लिये अमेरिका और भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। उसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपने-अपने ढंग से ढालने के जो प्रयास हो रहे हैं, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं मानव अधिकारों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, वैश्विक शांति, सामाजिक सोहार्द्र, धार्मिक और आर्थिक स्थिरता के प्रयास, लोकतंत्र की वैश्विक जिम्मेदारी का प्रतीक है। अमेरिका के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जिस तरह का विरोध पनप रहा है। उसने कई तरह की चुनौतियां पैदा कर दी हैं। ट्रम्प ने धार्मिक धुव्रीकरण को बढ़ाकर सत्ता पर पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है। कुछ इसी तरह की स्थिति भारत में भी है। जिसके कारण दोनों ही लोकतांत्रिक देशों की चर्चा होने लगी है। अमेरिका और भारत का लोकतंत्र सारी दुनिया के लिए अभी तक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता था। पिछले कुछ वर्षों में मानव अधिकार, सरकार के निर्णय और न्यायपालिका की भूमिका सरकारी दबाव में होने से कई तरह की विसंगतियां सामने आने लगी हैं। अमेरिका और भारत में गरीबी और अमीरी के बीच में असमानता बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ़-बार के जरिये अमेरिका का एकाधिकार बनाने की जो चेष्टा की जा रही है, उसके कारण वैश्विक तनाव बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है।

वैश्विक व्यापार संधि होने के बाद भी सभी देश विकल्प की तलाश कर रहे हैं। जिस तरह से प्रतिबंध और टैरिफ की राजनीति अमेरिका से शुरू हुई है, उसने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जो भूमिका पहिले थी, वह भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में अमेरिका और भारत को वैश्विक शांति को बनाये रखने के लिए अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। विशेष रूप से समाज में अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई बढ़ रही है। सारी दुनिया के देशों का कर्ज बढ़ा है। सारी दुनिया में पिछले 20 वर्षों में तेजी के साथ महंगाई बढ़ी है, रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमीरी और गरीबी के बीच में संतुलन बनाए रखने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं मानव अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका और भारत जैसे देशों की है। जहां आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में है।

आज का इतिहास

1862 संघीय संविधान और राष्ट्रपति पद को स्थायी घोषित किया गया।
1878 अमेरिका के कनेक्टिकट में पहली टेलीफोन डायरेक्टरी जारी की गई।
1916 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और फ्रांस के बीच अत्यंत भयानक युद्ध आरंभ हुआ। यह लड़ाई वरडन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है।
1918 पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की एकमात्र तोता प्रजाति कैरोलिना परकेट , विलुप्त हो गई जब सिनसिनाटी चिड़ियाघर में अंतिम रूप से कैद में मृत्यु हो गई।
1919 बवेरियन समाजवादी कर्ट ईस्नर, जिन्होंने जर्मन क्रांति का आयोजन किया था, जिन्होंने विटल्सबैच राजशाही को उखाड़ फेंका और एक गणतंत्र के रूप में बावरिया की स्थापना की।
1921 रेजा खान ने तेहरान को ईरान में खुद को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए जब्त कर लिया, जिससे अंतत: पहलवान राजवंश की स्थापना हुई।
1925 ब्राजील के एक डायनामाइट डिपो में 621 की मौत हुई।
1932 आंद्रे तार्डिए तीसरी बार फ्रांस के प्रधानमंत्री बने।
1948 बिल फ्रांस, सीनियर और कई अन्य रेस कार चालकों ने NASCAR की स्थापना की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टॉक कार रेसिंग के शासी निकाय थे।
1952 पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में प्रदर्शनकारी, बंगाली भाषा को अनौपचारिक भाषा के रूप में स्थापित करने की मांग करते हुए सैन्य संघर्ष में उतर गए।
1958 ब्रिटिश कलाकार गेराल्ड होल्टोम ने परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान के लिए एक लोगो डिज़ाइन किया जो कि आमतौर पर शांति प्रतीक के रूप में जाना जाता है।
1965 न्यूयॉर्क शहर के ऑडबोन बॉलरूम में भाषण देते समय काले राष्ट्रवादी मैल्कम एक्स की हत्या कर दी गई थी।
1971 साइकोट्रोपिक पदार्थ पर कन्वेंशन, मनोचिकित्सा दवाओं को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे वियना में प्लेनिपोटेंटियरीज के एकोफेक्शन पर हस्ताक्षर किया गया था।
1973 गलती से इजरायली हवाई क्षेत्र में भटकने के बाद, लीबिया अरब एयरलाइंस की उड़ान 114 को दो इजरायली लड़ाकू विमानों ने मार गिराया था।
1986 दक्षिण अफ्रीका सरकार ने जोहान्सबर्ग और डरबन अश्वेतों के लिए खोल दिए।
1996 सोयूज टीएम -23 अपनी कक्षा में लॉन्च हो गया।

क्या एआई के क्षेत्र में दुनिया को पछाड़ पाएगा भारत?

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे वैश्विक एआई सम्मेलन में दो दिन से चल रहे विचार मंथन से एक बात उभर कर आई है कि एआई के समक्ष खड़ी चुनौतियों के हल के लिए दुनिया भारत की ओर निहार रही है। देखना होगा कि सम्मेलन के अंत में दिल्ली डिक्लेरेशन से क्या निकल कर आता है। लेकिन यहां एक ओर बात की आवश्यकता महसूस हुई कि भारत को यदि इस क्षेत्र में नेतृत्व हासिल करना है तो बड़े निवेश और सरल तथा प्रभावी नीतियों की भी जरूरत है।

देखा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अब केवल नई तकनीक का आकर्षण नहीं रही, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुकी है। दुनिया के बड़े देश इसे रणनीतिक साधन की तरह देख रहे हैं। डाटा, कंप्यूटिंग शक्ति और उन्नत चिप आज के दौर का नया तेल बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत के सामने मूल प्रश्न यह है कि वह एआई की दौड़ में केवल उपभोक्ता बन कर रहेगा या निर्माता और नेता की भूमिका निभाएगा।

भारत ने पहले भी तकनीकी मोड़ पर सही फैसले लेकर इतिहास बदला है। नब्बे के दशक में सूचना तकनीक और सॉफ्टवेयर सेवाओं पर जोर देने से लाखों रोजगार बने, भारतीय कंपनियां दुनिया भर में छा गईं और देश को नई पहचान मिली। आज एक वैसा ही मोड़ फिर सामने है, लेकिन इस बार दांव कहीं बड़ा है। एआई न केवल सेवाओं को, बल्कि कारखानों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, दवा उद्योग, परिवहन और ऊर्जा व्यवस्था तक को बदल सकती है।

यह समझना जरूरी है कि एआई एक ही तरह की चीज नहीं है। उपभोक्ता एआई, जैसे चैट टूल या मनोरंजन आधारित अनुप्रयोग, तेजी से लोकप्रिय होते हैं, पर इन पर अक्सर कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा हो जाता है। इसके विपरीत औद्योगिक एआई हर क्षेत्र के लिए अलग समाधान मांगती है। हर उद्योग का अपना डाटा, अपनी समस्या और अपना कामकाज होता है। इसलिए क्षेत्र विशेष मॉडल बनते हैं। यही भारत की ताकत बन सकती है, क्योंकि यहां उद्योगों की विविधता और पैमाना दोनों मौजूद हैं।

उदाहरण के लिए दो पहिया वाहन उद्योग को लें। भारत दुनिया के सबसे बड़े दो पहिया बाजारों में है। यह क्षेत्र रोजगार, शहरीकरण और आय वृद्धि से जुड़ा है। अब इलेक्ट्रिक दो पहिया का चलन भी बढ़ रहा है। ऐसे में एआई आधारित मांग अनुमान, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता जांच और आपूर्ति प्रबंधन से भारी लाभ हो सकता है। मशीन लर्निंग सिस्टम खराबी का पहले ही संकेत दे सकते हैं। इससे

ठहराव घटता है, लागत कम होती है और उत्पादन तेज होता है।

दवा उद्योग में भी अवसर विशाल हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है, पर गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती रहता है। एआई आधारित विजन सिस्टम उत्पादन के दौरान सूक्ष्म दोष पकड़ सकते हैं। डाटा विश्लेषण से प्रक्रिया स्थिर रखी जा सकती है। रोबोटिक ऑटोमेशन दोहराव वाले काम सुरक्षित और सटीक तरीके से कर सकता है। इससे भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी और ऊंचे मूल्य वाले बाजार खुलेंगे।

लेकिन एआई की ताकत केवल सॉफ्टवेयर से नहीं आती, इसके लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति चाहिए, जो उन्नत चिप यानी जीपीयू से मिलती है। ये चिप बहुत महंगी होती हैं। एक उन्नत जीपीयू की कीमत लाखों रुपये तक जा सकती है। भारत ने हजारों जीपीयू लगाए हैं और डाटा केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष डाटा केंद्रों ने बिजली ग्रिड से भारी मात्रा में बिजली ली, जो किसी बड़े शहर की मांग के बराबर बैठती है। आने वाले वर्षों में यह मांग कई गुना बढ़ सकती है। यह भारत की बढ़ती डिजिटल क्षमता का संकेत है, पर साथ ही ऊर्जा चुनौती का भी।

अगर भारत को एआई में अग्रणी बनना है तो केवल कुछ हजार जीपीयू काफी नहीं होंगे। अमेरिका आज भी इस क्षेत्र में आगे है। उसके पास विशाल डाटा केंद्र क्षमता है और वह उन्नत जीपीयू की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण वह तकनीकी बढ़त बनाए हुए है। चीन को रोकने की रणनीति में भी चिप आपूर्ति अहम रही है।

चीन ने भी इस दौड़ को बहुत पहले समझ लिया था। उसने चिप निर्माण में भारी निवेश किया। उसकी बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने एआई चिप बना रही हैं। भले वे अभी सबसे उन्नत स्तर पर न हों, पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी बड़ी तकनीकी कंपनियां खुद चिप डिजाइन में उतर चुकी हैं। ऐसे माहौल में यदि भारत केवल पुराने स्तर की चिप बनाता रह गया तो वह पीछे छूट सकता है।

तो क्या समाधान है? क्या हमें अपनी आकांक्षा घटा लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत अभी विकसित देशों से कम है। जैसे जैसे लोग समृद्ध होंगे, उन्हें घरों में अधिक बिजली चाहिए होगी। अगर एआई के कारण बिजली महंगी हुई तो जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। यह चिंता सही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पीछे हट जाएं।

दरअसल जरूरत बड़े सोच की है। भारत को एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, घरेलू चिप निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देना। इसके लिए नीति समर्थन, निवेश और कौशल विकास जरूरी है। दूसरा, ऊर्जा ढांचा मजबूत करना। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बेहतर ग्रिड और भंडारण तकनीक पर जोर देना होगा ताकि डाटा केंद्रों की मांग पूरी हो सके।

इसके साथ ही एआई का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। मध्यम और छोटे उद्योगों तक भी पहुंचे। इसके लिए साझा प्लेटफॉर्म, क्लाउड ढांचा और क्षेत्र विशेष समाधान जरूरी हैं। सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों को मिल कर काम करना होगा। शोध संस्थान मॉडल विकसित करें, उद्योग वास्तविक समस्याएं और डाटा दें, और सरकार नियम, प्रोत्साहन तथा अवसंरचना दे।

भारत को ऐसे नेतृत्व की भी जरूरत है जो अलग अलग पक्षों को जोड़ सके और भरोसा बना सके। एआई को नौकरी छीनने वाली नहीं, बल्कि नई क्षमता देने वाली तकनीक के रूप में समझाना होगा। कौशल प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण और शिक्षा सुधार पर जोर देना होगा।

बहरहाल, अब सवाल यह है कि एआई की दिशा कौन तय करेगा? अगर भारत ने समय रहते साहसिक फैसले लिए, चिप निर्माण, ऊर्जा ढांचा और औद्योगिक एआई पर जोर दिया, तो वह केवल तकनीक का बाजार नहीं रहेगा, बल्कि दिशा देने वाला देश बन सकता है। आईटी क्रांति ने भारत को विश्व मंच पर जगह दी थी। एआई और उन्नत कंप्यूटिंग भारत को आर्थिक शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता के नए दौर में पहुंचा सकती है। अवसर हमारे सामने है। अब निर्णय और क्रियान्वयन हमारी जिम्मेदारी है।

क्या रहमान सरकार में सुधरेंगे भारत-बंगलादेश संबंध?

राज कुमार सिंह

भारत के सबसे अप्रत्याशित और नए दुश्मन देश बंगलादेश में नव निर्वाचित सरकार पदारूढ़ हो गई। 17 साल बाद ब्रिटेन से स्वदेश लौट कर चुनाव में बंगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बी.एन.पी.) का नेतृत्व करने वाले तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था, पर भारत का प्रतिनिधित्व किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। भारत की ओर से शुभकामना पत्र देते हुए बिरला ने तारिक को यात्रा का निमंत्रण भी दिया। अगस्त, 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में भारत-बंगलादेश संबंधों में कटुता चरम पर दिखी। बंगलादेश में हिंदू नागरिकों, उनके धर्मस्थलों एवं घरों-व्यावसायिक ठिकानों को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया। हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं भी हुईं। जिस भारत के सहयोग से 1971 में पाकिस्तान के शिकंजे और दमनचक्र से मुक्त हो कर बंगलादेश स्वतंत्र देश बन पाया, उसी के विरोध में यूनुस सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती तक चली गई। बेशक जेन-जी के विद्रोह से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत द्वारा शरण से भी परस्पर कटुता बढ़ी, लेकिन एक दोस्त देश का दुश्मनों से हाथ मिला लेना बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि दोनों के बीच लंबी सीमा है। इसी कटुता के परिणामस्वरूप बंगलादेश ने पाकिस्तान के उकसावे में आ कर टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का बहिष्कार भी कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्ता परिवर्तन से भारत-बंगलादेश संबंध सुधरेंगे? बेशक तारिक रहमान ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कुछ नहीं कहा, जिससे आशंकित हुआ जाए। ज्यादातर जानकार उनके 31 सूत्रीय एजेंडा को बेहतर संबंधों की संभावना का ही संकेत मानते हैं। जमात-ए-इस्लामी पार्टी और शेख हसीना सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जेन-जी की नैशनल सिटीजन पार्टी (एन.सी.पी.) की तरह भारत विरोधी कार्ड खेलने से तारिक ने परहेज ही किया। डिजिटल डोमेन और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस आदि के जरिए तारिक बंगलादेश को रेनबो नेशन बनाने का सपना दिखा रहे हैं, जिसमें भारत से संबंध सुधार की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। तारिक मंत्रिमंडल में एक हिंदू और एक बौद्ध को भी शामिल किया गया है, लेकिन यह भी सच है कि वह जिया उर रहमान और खालिदा जिया के राजनीतिक वारिस हैं, जो भारत विरोध की ही राजनीति करते रहे। यह तो ऐतिहासिक सच है कि बंगलादेश के जनक माने जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्त रहे, जिन्हें पहले जिया उर रहमान और फिर खालिदा जिया राजनीतिक चुनौती देती रहीं। यह भी कि जिया उर रहमान और खालिदा जिया के शासन में भारत-बंगलादेश संबंध कभी भी सहज नहीं रहे। संसद के जिन चुनावों में प्रचंड जीत के जरिए तारिक रहमान ने सत्ता हासिल की है, उनमें शेख हसीना की अवामी लीग को भाग नहीं लेने दिया गया। शेख हसीना इन चुनावों को मानने को भी तैयार नहीं हैं। जाहिर है, यूनुस सरकार द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण का आग्रह तारिक सरकार भी दोहराएगी। लगभग डेढ़ साल से भारत में रह रहीं शेख हसीना के प्रत्यर्पण का फैसला निश्चय ही भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके तख्तापलट के पीछे अन्य देशों की भूमिकाओं की चर्चा भी आम रही है। ऐसे में दोनों परिवारों की परंपरागत कटुता के अलावा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भी तारिक सरकार के लिए शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा गरमाए रखना अनुकूल साबित होगा। तारिक के पास अपने पिता जिया और मां खालिदा जैसा राजनीतिक अनुभव नहीं है, पर विदेश प्रवास के चलते देश के लिए नए सपने हो सकते हैं।

क्या राहुल गांधी 'विशेषाधिकार की भावना' से ग्रस्त हैं?

बलबीर पुंज

समय कई बार ऐसी चौंकाने वाली समानताएं हमारे सामने रख देता है, जो राजनीतिक-जीवन को नए तरीके से समझने का अवसर देती हैं। आज की उथल-पुथल भरी वैश्विक राजनीति में 2 ऐसे व्यक्तित्व-अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और देश के नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय होने के बावजूद दोनों का बदलते भारत को देखने का दृष्टिकोण लगभग एक जैसा है। यह इसलिए भी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि ट्रम्प विदेशी हैं और राहुल भारत के शीर्ष नेताओं में एक। दोनों ही उस नए भारत से असहज हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी हीनभावना के दुनिया से अपनी शर्तों पर आत्मविश्वास के साथ संवाद कर रहा है। एक ओर ट्रम्प के रूप में वह दृष्टिकोण है, जो केवल लेन-देन पर आधारित है और वैश्विक व्यवस्था में अपनी धमक बरकरार रखने के लिए प्रयासरत है, वहीं राहुल एक ऐसे राजनीतिक वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने स्वतंत्र भारत की सत्ता को अपनी विरासत मानकर पश्चिमी स्वीकृति को ही कूटनीतिक सफलता का पर्याय समझा है।

लोकतंत्र में आलोचना स्वाभाविक है। लेकिन यह चिंताजनक तब हो जाता है, जब देश का कोई प्रमुख नेता बाहरी पूर्वाग्रहों को अंतिम सत्य मानकर उसे दोहराने लगता है। राहुल द्वारा ट्रम्प के 'मृत अर्थव्यवस्था' कथन का समर्थन, मोदी सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान युद्धविराम में अमरीकी मध्यस्थता के ट्रम्प के दावे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पर 'नरेंद्र-सरेंडर' जैसी टिप्पणी कर दी, जबकि भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से साफ इंकार कर चुका था, जिसकी पाकिस्तान भी गवाही देता है।

निस्संदेह, सशक्त विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है। लेकिन अपने ही देश के खिलाफ बाहरी आरोपों को प्रामाणिक मानकर पेश करना खतरनाक प्रवृत्ति है। भारत इसी परतंत्र मानसिकता के कारण शताब्दियों तक विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा था। बात राहुल के वक्तव्यों तक भी सीमित नहीं है। वह संसद जैसी गंभीर संस्था को अपने

आचरण से कई बार उपहास का विषय बना चुके हैं। हाल ही में लोकसभा में उन्हें जनरल (सेवानिवृत्त) मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा से उद्धरण देने, जो न तो सार्वजनिक है और न ही रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, से संसदीय नियमों के तहत रोका गया। उन्होंने संसदीय परंपराओं का सम्मान करने की बजाय इसे संसदीय कार्रवाई में व्यवधान डालने का मुद्दा बना लिया। बार-बार के स्थगन, लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और योजनाबद्ध टकराव को लोकतांत्रिक प्रतिरोध का नाम दिया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी खुलासा किया कि संसद में चर्चा के समय प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अप्रिय हरकत करने की कोशिश की जा रही थी।

राहुल की यह 'अराजक' शैली नई नहीं है। 2018 में लोकसभा में प्रधानमंत्री को जबरन गले लगाने के बाद अपने सहयोगियों को आंख मारने की घटना आज भी जेहन में ताजा है। नाटकीयता गंभीर राजनीति का पर्याय नहीं हो सकती, वह संस्थागत गरिमा को आहत करती है। संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री का जबरन हाथ पकड़कर संयुक्त प्रैस वार्ता का प्रयास भी इसी मानसिकता का विस्तार था। जाने-अनजाने में राहुल देश-विरोधियों के हाथों में भी खेलने लगते हैं। सितम्बर 2024 की अमरीका यात्रा के दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत में सिख समुदाय की पहचान खतरे में है। इस बयान को खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने एजैंडे के समर्थन में तुरंत लपक लिया। इससे पहले वर्ष 2023 में राहुल द्वारा ब्रिटेन यात्रा के दौरान दिए गए वक्तव्यों का आशय था कि 'भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है' और उसे बचाने के लिए 'पश्चिमी हस्तक्षेप' अपेक्षित है। अक्सर, विदेशों में दिए गए ऐसे वक्तव्य घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते और वे भविष्य में देश के शत्रुओं के प्रचार-तंत्र का हथियार बन जाते हैं।

राहुल इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वे 'विशेषाधिकार की भावना' से ग्रस्त हैं? क्या वह मानते हैं कि केवल उन्हें ही अपने मुताबिक 'लोक' (जनमानस) और 'तंत्र' (मीडिया-न्यायालय सहित) चलाने का 'दैवीय अधिकार' है? असल में उनका यह चिंतन न तो 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद पनपा है और न ही यह भाजपा-आर.एस.एस. तक सीमित है। 27 सितम्बर, 2013 को उन्होंने अपनी ही केंद्र सरकार के एक अध्यादेश को 'बकवास' बताते हुए उसे सार्वजनिक रूप से 'फाड़कर फैंक देने' की बात कही थी। इसी ठसक से 2019 की एक चुनावी रैली में उन्होंने 'मोदी' उपनाम वाले सभी लोगों को 'चोर' कहा, तो 2024 की एक सभा में भाजपा के दोबारा सत्ता में आने पर देश के 'आग में जल उठने' की आशंका जताई। लगातार चुनावी पराजयों के बाद वह चुनाव आयोग और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं।

राहुल कांग्रेस की उस व्यवस्था से आते हैं, जिसमें भारतीय परंपरा-स्वाभिमान उत्सव का नहीं, बल्कि तथाकथित पिछड़ेपन, उत्पीडऩ और महिला-विरोध का प्रतीक माना जाता है। दशकों तक भारतीय संस्कृति के प्रति हीन-भावना रखने वालों को मतदाता लगातार खारिज कर रहे हैं। वर्ष 2014 से ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को जनादेश मिल रहा है, जो सभ्यतागत पुनरुद्धार, कल्याणकारी वितरण और रणनीतिक दृष्टि से ईमानदार है। भारत अभूतपूर्व स्तर पर आधारभूत संरचना का निर्माण, डिजिटल माध्यम से जनहित योजनाओं का विस्तार, रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रहा है। ट्रम्प अपने व्यवहार-वक्तव्यों से भारत का बहुत अधिक नुकसान नहीं कर सकते। एक तो उनका कार्यकाल सीमित है, दूसरा, भारत इतना सामर्थ्यवान हो चुका है कि वह किसी भी बड़ी वैश्विक शक्ति का विरोध सहते हुए सिर ऊंचा करके जी सकता है। परंतु भारत के भीतर-विशेषकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए जाने वाले गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देश को गंभीर और गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं।

पंजाब कांग्रेस की 'नई एकजुटता': अब नजरें 2027 पर

रविंदर सिंह रॉबिन

पंजाब की राजनीति के उतार-चढ़ाव भरे अखाड़े में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दबाव के बीच एकजुट होने की कला में महारत हासिल कर ली है, ठीक उसी तरह, जैसे कोई परिवार तूफान के दौरान एक साथ खड़ा हो जाता है। यह शाश्वत गाथा एक बार फिर 16 फरवरी, 2026 को सामने आई, जब पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नेता रणनीतिक 'डिनर मीटिंग' के लिए चंडीगढ़ में प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर एकत्रित हुए। पंजाब विधानसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता बाजवा द्वारा आयोजित इस सभा ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एकजुटता का एक शक्तिशाली संकेत दिया।

बाजवा, जो अप्रैल, 2022 से विपक्ष के नेता का पद संभाल रहे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, ने हालिया अंतर्कलह के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उपस्थित लोगों में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, और सुखजिंदर सिंह रंधावा, भारत भूषण आशू, गुरजीत सिंह औजला, सुखजिंदर सिंह सरकारिया, ओम प्रकाश सोनी और जसबीर सिंह डिंपा जैसे कई दिग्गज शामिल थे। यह बैठक पार्टी के ऐतिहासिक पैटर्न को दोहराती है- जब दाव ऊंचे होते हैं, तो आंतरिक प्रतिद्वंद्विता एकजुटता में बदल जाती है। यदि 2024 के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें, जहां पंजाब की 13 संसदीय सीटों पर कड़ा मुकाबला था, तो टिकट बंटवारे के दौरान कांग्रेस के दावेदारों में तीखी झड़प हुई थी। लेकिन एक बार जब हाईकमान ने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया, तो वे एकजुट हो गए और 7 सीटें हासिल कीं, जो कि सबसे अधिक संख्या थी। आम आदमी पार्टी (आप) को 3, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को 1 और निर्दलीयों को 2 सीटें मिलीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का खाता भी नहीं खुला।

यह जीत 2017 के विधानसभा चुनावों की याद दिलाती है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस से 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री (2002-07 और 2017-21) रहे, उन्होंने नवजोत सिद्धू के साथ विवाद और खुद को दरकिनार किए जाने के बाद सितम्बर 2021 में पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने अक्तूबर 2021 में पंजाब लोक कांग्रेस बनाई, 2022 के चुनावों के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया और फिर 19 सितम्बर, 2022 को अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया और आधिकारिक तौर पर उसमें शामिल हो गए।

'डिनर डिप्लोमेसी' (भोज की राजनीति) भारतीय राजनीति में एक समय-परीक्षित रणनीति है, जो सार्वजनिक चकाचौंध से दूर गठबंधन बनाने और दरारों को भरने के लिए सांझा भोजन की आत्मीयता का लाभ उठाती है। चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे आलोचकों को पंजाबी व्यंजनों-जैसे कि 'मक्खन वाला सरसों का साग और मक्की की रोटी' पर आमंत्रित करके, इस कार्यक्रम ने एकजुटता का एक ऐसा नैरेटिव बुना, जो गुटबाजी की धारणाओं को चुनौती देता है। यह नेताओं के मानवीय पक्ष को सामने लाकर काम करता है, जिससे 'ऑफ द रिकॉर्ड' बातचीत के जरिए अहंकार को सुलझाने और रणनीति बनाने में मदद मिलती है, जबकि लीक हुई तस्वीरें या बयान मीडिया में 'सब ठीक है' की कहानी को पुख्ता करते हैं, जिससे कार्यकर्त्ताओं का मनोबल और मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है।

भोज के दौरान छनकर आई बातों ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया-हल्की-फुल्की गपशप हुई, जैसे वड्क्षडग़ के अंदाज पर चुटकुले और चन्नी द्वारा विपक्ष की सीट को लेकर किया गया मजाक। यह सब अच्छे हंसी-मजाक में हुआ, जिससे पुराने तनाव को कम करने में मदद मिली। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसी दोस्ताना बातचीत दिखाती है कि कैसे एक साधारण भोजन झगड़ों को दोस्ती में बदल सकता है और पार्टी की भविष्य की लड़ाइयों के लिए एकजुटता की एक मजबूत कहानी लिख सकता है। आज, 2022 में चुनी गई पंजाब विधानसभा में, कांग्रेस 16 सीटों के साथ आधिकारिक विपक्ष है, जबकि 'आप' के पास 94 सीटों का भारी बहुमत है। प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर एकजुटता का हालिया प्रदर्शन किसी भी सत्ता-विरोधी लहर का लाभ उठाने के पार्टी के संकल्प को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, यह नई एकजुटता अंतर को पाटने और 'आप' के गढ़ को कड़ी चुनौती देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

जैसा कि बाजवा की डिनर डिप्लोमेसी रेखांकित करती है, जब 'दबाव बढ़ता है, तो पंजाब कांग्रेस घड़ी की सूइयों की तरह एक साथ खड़ी हो जाती है। अब सभी की निगाहें 2027 पर टिकी हैं, जहां यह एकजुटता सत्ता में विजयी वापसी की पटकथा लिख सकती है और राज्य के राजनीतिक सिंहासन पर फिर से दावा कर सकती है। आने वाला वर्ष यह परीक्षण करेगा कि क्या कांग्रेस आंतरिक एकजुटता को चुनावी गति में बदल पाती है और पंजाब की राजनीति में अपना ऐतिहासिक प्रभाव वापस पा सकती है?

एआई को बढ़ावा जरूर दें, लेकिन समझदारी से

प्रो अश्विनी महाजन

भारत एआइ से होने वाले प्रौद्योगिकीय बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन एआइ टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बड़ी कंपनियों के पास होने के साथ-साथ डाटा भी, जो इन बड़ी एआइ कंपनियों को मजबूत बना रहा है, हमारे जैसे विकासशील देशों से मिल रहा है। ऐसे में हम डिजिटल उपनिवेशीकरण के मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। हालांकि, एआइ टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का नियंत्रण बना हुआ है, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआइ) के निर्माण और बड़े पैमाने पर पहचान-प्रमाणीकरण में एआइ/डाटा तकनीकों के उपयोग में विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका निभायी है। जैम ट्रिनिटी, यानी जन धन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल बैंकिंग की मदद से सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), गरीबों के लिए घर और कई दूसरी कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। हमें नये कानून भी मिले हैं, जैसे विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) एक्ट, 2025, जो एआइ इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सरकारी योजना में भ्रष्टाचार कम करने में मदद कर रहे हैं। अस्पतालों में एआइ एक्स-रे, स्कैन और रिपोर्ट के विश्लेषण में तेजी से मदद कर रहा है। जानलेवा बीमारियों का जल्दी पता लगाना और उनका अनुमान लगाना भी एआइ की वजह से मुमकिन हुआ है। हम एआइ समर्थित एप्स का इस्तेमाल कर अपनी रोजाना की शारीरिक गतिविधि को चला सकते हैं। रोजगार एआइ का एक बड़ा शिकार है, और सभी क्षेत्रों में नौकरियों का सफाया एक सच्चाई बन चुकी है। मीडिया, मनोरंजन, कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र भी एआइ का असर झेलने लगे हैं। बड़ी फैक्ट्रियां एआइ समर्थित कंप्यूटर प्रोग्रामों की मदद से सामान बनाती हैं, जिससे भारी बेरोजगारी हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26 में बताया गया है कि भारत के आकार और प्रति व्यक्ति आय उसके मुकाबले कम होने की वजह से भारतीय श्रम बाजार में एआइ का असर ज्यादा होगा। इसमें चेतावनी दी गयी है कि कंपनियों द्वारा एआइ को बिना सोचे-समझे अपनाने से सभी की हालत खराब हो जायेगी और देश की ग्रोथ क्षमता को नुकसान होगा। सर्वेक्षण में सरकार, निजी क्षेत्र और अकादमिक जगत के बीच और ज्यादा सक्रिय सहयोग की बात कही गयी है, ताकि एआइ से उत्पादकता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा फैले। इसलिए नयी टेक्नोलॉजी को बिना सोचे-समझे नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे में, एआइ के लिए सही विनियमन करने की जरूरत है। स्वामित्व की दृष्टि से एआइ पर अमेरिका और चीन का दबदबा है, जबकि ज्यादातर उपयोगकर्ता भारत समेत विकासशील देश हैं, साथ ही वे इन एआइ प्लेटफॉर्म द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे डाटा का स्रोत भी हैं। भारत जैसे विकासशील देश विदेशी मालिकाना हक वाले एआइ प्लेटफॉर्म पर निर्भर बने हुए हैं और इस प्रक्रिया में डाटा संप्रभुता भी खो रहे हैं। इन टेक दिग्गजों के मालिकाना हक वाले एआइ के दबदबे की वजह से छोटे और कुटीर उद्योग, सेवा एंटरप्राइज और कर्मी नुकसान में हैं। हालांकि एआइ की अहमियत को देखते हुए इसे रोका नहीं जाना चाहिए, पर इसके विनियमन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। हमें इस टेक्नोलॉजी को समझदारी से बढ़ावा देने की जरूरत है। गूगल और दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, जो ज्यादातर अमेरिका और चीन की हैं, एआइ के लिए जरूरी ज्यादातर डाटा नियंत्रित करती हैं। ऐसी स्थिति छोटे खिलाड़ियों के लिए एंट्री में बड़ी रुकावटें पैदा करती है। अपनी कमियों के बावजूद एआइ के लाभों को देखते हुए नीति निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि एआइ कैसे समानता के साथ मानवता की सेवा कर सकता है। इसके लिए देश में एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआइ) की जरूरत है, जिसके माध्यम से आम लोगों के लिए, समानता के आधार पर एआइ तकनीकों का विकास और उपयोग सुगम बनाया जा सके। अच्छी खबर यह है कि संचार क्रांति के कारण भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। स्वदेशी 4-जी नेटवर्क का विस्तार लगभग पूरे देश में किया गया है और देश ने अपना स्वदेशी 5-जी नेटवर्क भी विकसित कर लिया है। भारत को सबसे सस्ते डाटा की भूमि होने का गौरव भी प्राप्त है। देश को स्वदेशी एआइ प्लेटफॉर्म्स की भी जरूरत है, जो केवल विदेशी तकनीकों पर निर्भर न हों, बल्कि देश के डाटा, भाषाओं, आवश्यकताओं और सुरक्षा हितों के अनुरूप एआइ के विकास, तैनाती और प्रबंधन के लिए स्वदेशी फ्रेमवर्क उपलब्ध करायें।

काले चने गुड़ के साथ खाने से एनीमिया जल्द खत्म हो जाता है

खून में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की कमी को एनीमिया कहते हैं। कई बार शरीर रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन बना नहीं पाता और कई बार ज्यादा खून बह जाने से शरीर में इनकी कमी हो जाती है। एनीमिया को एक तरह की बीमारी माना जाता है। ये बीमारी ज्यादातर महिलाओ को होती है और उनमें इसकी एक मुख्य वजह मासिक धर्म होता है। आमतौर पर पुरुषों में 100 मिली ग्राम खून में 13.5 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन और महिलाओं में 100 मिली ग्राम खून में 12 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो तो इसे एनीमिया की स्थिति कहते हैं। कई बार एनीमिया के मरीजों में बाहर से कोई लक्षण नहीं नजर आते या हल्के-फुल्के लक्षण नजर आते हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। खून की सीबीसी जांच द्वारा इस बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

एनीमिया का कारण

एनीमिया का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 3-5 ग्राम आयरन होता है। शरीर में इसकी मात्रा कम होने पर खून कम बन पाता है और एनीमिया हो जाता है। कई बार ज्यादा मात्रा में खून बह जाना भी एनीमिया का कारण बनता है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की अधिकता से भी एनीमिया हो सकता है इसलिए कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थों का बहुत अधिक सेवन भी शरीर के लिए खतरनाक है।

एनीमिया से बचाव

एनीमिया से बचाव के लिए आपको अपनी जीवनशैली में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। एनीमिया मुख्यत : शरीर में खून की कमी ही है इसलिए इससे बचाव के लिए ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिससे शरीर में खून की मात्रा बढ़े जैसे- चुकंदर, गाजर, पालक, टमाटर, बथुआ और अन्य हरी सब्जियां। के साथ-साथ काले चने और गुड़ में भी आयरन भरपूर होता है। रोजाना सुबह भीगे हुए काले चने गुड़ के साथ खाने से एनीमिया जल्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सब्जी बनाने के लिए लोहे की कड़ाही का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी शरीर में आयरन की कमी दूर होती है। शरीर में आयरन की ज्यादा कमी होने पर आप चिकित्सक की सलाह से आयरन की गोलियां भी ले सकते हैं।

एनीमिया के लक्षण

काम के दौरान जल्दी थक जाना
दिनभर कमजोरी महसूस होना
त्वचा पीली पड़ना
सीढ़ी चढ़ते हुए चक्कर आ जाना
सीने और सिर में दर्द होना
तलवों और हथेलियों का ठंडा हो जाना

सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है किशमिश के पानी

किशमिश के पानी सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। इससे पेट की एक-दो नहीं बल्कि कई बीमारियां दूर हो जाती है। किशमिश में मौजूद तत्व शरीर की पूरी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और इससे आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाता है और कब्ज, गैस आदि की दिक्कत नहीं होती है। सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं, लेकिन किशमिश का पानी सेहत के लिए और भी फायदेमंद होता है। किशमिश में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि पानी के साथ मिलकर ज्यादा असरदार हो जाते हैं। इसके लिए रात के समय एक गिलास पानी में 8 से 10 किशमिश भिगोकर रख दें और सुबह इसे अच्छी तरह पीस लें। अगली सुबह किशमिश छान कर पानी को पीने लायक गरम करें और इसे खाली पेट पिएं। किशमिश का पानी पीने के बाद 30 से 35 मिनट तक इंतजार करें और फिर नाश्ता करें। किशमिश का पानी लीवर में बायोकैमिकल प्रोसेस शुरु करता है, जिससे खून तेजी साफ से होने लगता है। इसके अलावा किशमिश में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किशमिश का पानी पीने के और भी फायदे।

दांतों के लिए : किशमिश में ऑलियानॉलिक एसिड होता है जो कि फाइटोकेमिकल्स में से एक है और यह दांतों को केविटी और कई दिक्कतों से बचाता है। साथ ही किशमिश दांतों में बैक्टिरिया फैलने से रोकता है और दांतो को सुरक्षित रखता है। इसमें केल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह आपके दांतो को टूटने से बचाता है।

स्किन के लिए : किशमिश के पानी में फ्लेवेनॉइड्स एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्किन पर होने वाली झुर्रियों को तेजी से कम करने में सहायक है। यह बढ़ती उम्र के निशान को कम कर आपको जवां दिखने में मदद करता है।

सांसों की बदबू के लिए : किशमिश में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इससे बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता मिलती है और मुंह से आने वाली बदबू दूर होती है। इसके अलावा इसका उपयोग कई हेल्थ टॉनिक में भी किया जाता है।

पेट संबंधी रोगों के लिए : किशमिश के पानी से पेट की एक-दो नहीं बल्कि कई बीमारियां दूर हो जाती है। किशमिश में मौजूद तत्व शरीर की पूरी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और इससे आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाता है और कब्ज, गैस आदि की दिक्कत नहीं होती है। साथ ही इसके नियमित सेवन से थकान भी दूर रहती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है।

हार्ट प्रॉब्लम के लिए : हर रोज किशमिश का पानी उन लोगों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है जो अधिक कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से परेशान हैं और उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल किशमिश का पानी शरीर में ट्राईग्लिसेराइड्स के स्तर को कम करने में मददगार है। इससे आपके शरीर में हर्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है।

आंखों के लिए : किशमिश में पॉलीफेनॉलिक फायटोन्यूट्रिंस होते हैं जो कि एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं और यह आंखों की आई साइड को ठीक रखने में मदद करती है। इसमें कई तरह के एंटी बॉयटिक और एंटी ऑक्सीडेंट फिनॉलिक पायथोन्यूट्रियंट तत्व होते हैं जो कि बुखार को भी ठीक कर देते हैं।

संक्रमण से होती है आंखें लाल

आंख लाल होने की समस्या तब होती है जब आंख की सतह पर मौजूद रक्त वाहिकाएं फैलती हैं या चौड़ी होती हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी आंख में कोई बाहरी चीज चली जाती है या कोई संक्रमण होता है। आंख आमतौर पर कुछ समय के लिए लाल हो जाती हैं। इसके साथ आंख में दर्द, आंखों में खुजली, रिसाव, आंखों की सूजन और धुंधला दिखना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आंख लाल होने में या तो आंखों का पूरा सफेद हिस्सा लाल दिखने लगता है या कुछ रक्त वाहिकाएं सूज कर लाल हो जाती हैं। अगर आपकी आंख ठीक नहीं होती और लाली बढ़ती है, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं।

लक्षण

आंख में खुजली होना
आंख से ज्यादा आंसू आना
आंख से रिसाव होना
प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता
धुंधला दिखना
नजर कमजोर होना
एक या दोनों आंखों में किरकिराहट महसूस होना
देखने या पढ़ने के बाद असहजता महसूस होना

कारण

इन कारणों से लाल होती हैं आंखें
सूखे बाल
मिट्टी
ऐलर्जी
ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखाएं
आंख में हाल ही में चोट लगी है

अगर आप नजर में बदलाव, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, तेज सिरदर्द जैसे लक्षण अनुभव कर रहे हों।

ज्यादा दर्द हो रहा हो।
सिर पर चोट लगी हो।
किसी रसायन से आंख में चोट पहुंची हो

बचाव

आंखों को न मलें। आंखें मलने से इंफेक्शन व ऐलर्जी करने वाले बैक्टीरिया चले जाते हैं।

जोर से आंख मलने से कॉर्निया में खरोंच और सबकन्जंक्टिवाईटल हेमरेज हो सकता है।

धुएं, भाप, पराग, मिट्टी और क्लोरीन जैसे उत्तेजक पदार्थो से दूर रहें।

अपने कॉन्टैक्ट लेंस की सही से देखभाल करें।

कॉन्टैक्ट लेंस को ज्यादा समय तक न पहनें और इन्हें पहन कर न सोएं।

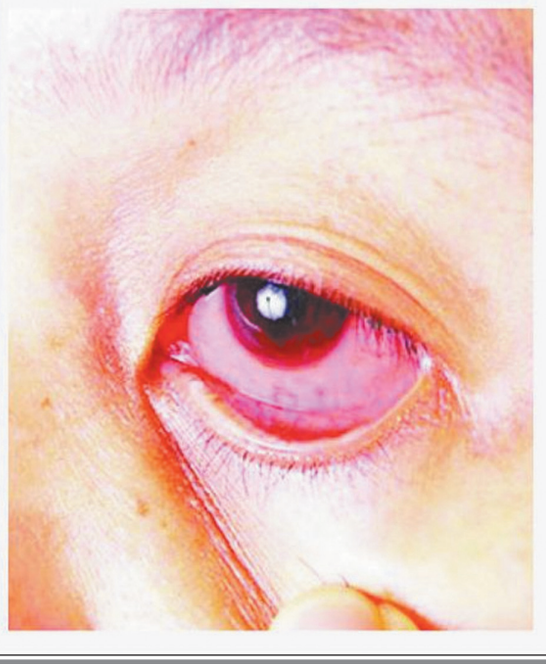

युवाओं में तनाव से बढ़ रहे हृदयाघात के मामले

भारतीय युवाओं में हृदयाघात की समस्या बढ़ती जा रही है और यदि इस समस्या पर रोक के उपाय नहीं किए गए तो यह महामारी का रूप ले कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार हृदय रोग की महामारी को रोकने का एकमात्र तरीका लोगों को शिक्षित करना है।

आम तौर पर दिल के दौरे का संबंध पहले बुढ़ापे से माना जाता था।लेकिन अब अधिकतर लोग उम्र के दूसरे, तीसरे और चौथे दशक के दौरान ही दिल की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। आधुनिक जीवन के बढ़ते तनाव ने युवाओं में दिल की बीमारियों के खतरे पैदा कर दिया है हालांकि अनुवांशिक और पारिवारिक इतिहास अब भी सबसे आम और अनियंत्रित जोखिम कारक बना हुआ है, लेकिन युवा पीढ़ी में अधिकतर हृदय रोग का कारण अत्यधिक तनाव और लगातार लंबे समय तक काम करने के साथ-साथ अनियमित नींद पैटर्न है। धूम्रपान और आराम तलब जीवनशैली भी 20 से 30 साल के आयु वर्ग के लोगों में इसके जोखिम को बढ़ा रही है।

ओपन हार्ट सर्जरी के मामले बढ़े

देश में हृदय अस्पतालों में दो लाख से अधिक ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है और इसमें सालाना 25 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।यह सर्जरी केवल तात्कालिक लाभ के लिए होती है। हृदय रोग के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए लोगों को हृदय रोग और इसके जोखिम कारकों के बारे में अवगत कराना महत्वपूर्ण है।

कोरोनरी हृदय रोग ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन इसके इलाज से लक्षणों का प्रबंधन करने, दिल की कार्यप्रणाली में सुधार करने और दिल के दौरे जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए जीवनशैली में परिवर्तन, दवाएं और नॉन-इंवैसिव उपचार शामिल हैं। अधिक गंभीर मामलों में इंवैसिव और शल्य चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।

समान लक्षण नहीं होते

सभी हृदय रोगियों में समान लक्षण नहीं होते हैं और एंजाइना छाती का दर्द इसका सबसे आम लक्षण नहीं है। कुछ लोगों को अपच की तरह असहज महसूस हो सकता है और कुछ मामलों में गंभीर दर्द, भारीपन या जकड़न हो सकता है। आमतौर पर दर्द छाती के बीच में महसूस होता है, जो बाहों, गर्दन, जबड़े और यहां तक कि पेट तक फैलता है, और साथ ही धड़कन का बढ़ना और सांस लेने में समस्या होती है।

अगर धमनियां पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती हैं, तो दिल का दौरा पड़ सकता है, जो हृदय की मांसपेशियों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। दिल के दौरे में होने वाले दर्द में पसीना आना, चक्कर आना, मतली और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी ने दर्ज कराया बयान

सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को बेगुनाह बताया। कोर्ट ने मामले में सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए अगली तारीख 9 मार्च निर्धारित की है। करीब आधे घंटे तक कोर्ट कक्ष का दरवाजा बंद करके मानहानि मामले में धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चली। इस दौरान अदालत परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कोर्ट कक्ष से लेकर बाहर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रही। भीड़ को नियंत्रित करने में सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। अब मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। जब बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे पहले वह लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे।

उगते सूरज की भूमि को प्रधानमंत्री मोदी की बधाई

नईदिल्ली। 20 फरवरी का दिन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज ही के दिन वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। उगते सूरज की भूमि और पहाड़ी लोगों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध ये दोनों राज्य सामरिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से भारत के अभिन्न अंग हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य की स्थापना दिवस पर बधाई दी और कामना की कि आने वाले समय में ये राज्य विकास की नयी ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मनोरम दृश्यों और असाधारण सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसके उत्साही और मेहनती नागरिक राष्ट्र की प्रगति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही राज्य की विविध जनजातीय संस्कृति राष्ट्र को अपार समृद्धि प्रदान करती है।

एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन

नई दिल्ली। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज उग्र प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के दौरान अपनी शर्ट उतारे भी देखा गया। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर उग्र विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारत मंडपम के अलग-अलग पवेलियन में जाकर प्रदर्शन करते देखा गया। मौके पर मुस्तैद दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लेकर शिखर सम्मलेन के आयोजन से दूर किया। वहीं, सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय युवा कांग्रेस ने लिखा- जब विदेश नीति में झुकाव, कॉरपोरेट दबाव और चुप्पी हावी हो तो साफ है, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं!!

आंध्र प्रदेश विधान परिषद में जमकर हंगामा

अमरावती। आंध्र प्रदेश विधान में शुक्रवार को हंगामे की स्थिति बन गई। परिषद के अध्यक्ष कोय्ये मोशन राजू ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। दरअसल, वाईएसआरसीपी के सदस्य श्री वेंकटेश्वर स्वामी की तस्वीरों को कथित तौर पर दिखाने को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। हंगामा तब शुरू हुआ जब सभापति ने टीटीडी को घी की आपूर्ति करने वाले मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू परिवार के स्वामित्व वाले हेरिटेज फूड्स से कथित तौर पर जुड़े तिरुपती लड्डू प्रसादम और इंदापुर डेयरी पर कुंभा रवि बाबू, डी माधव राव और एस मंगम्मा की चर्चा की याचिका खारिज कर दी। राजू ने विपक्षी विधायकों के विरोध प्रदर्शन के बीच कहा चर्चा को अस्वीकार किए जाने के बाद चर्चा की मांग करना सही नहीं है, इस बीच, राज्य के वित्त मंत्री पी. केशव ने देवता की मूर्तियों के कथित प्रदर्शन को आपत्तिजनक करार दिया और कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

देश से जो गद्दारी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा : एलजी

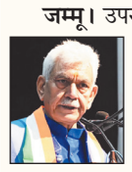

जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चेतावनी दी है कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों की गंभीरता से जांच करेंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीरवार को कश्मीरी पंडितों की सम्मान के साथ घर वापसी को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा कि कश्मीरी पंडितों की पूरी इज्जत और सुरक्षा के साथ वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है। उन्होंने कहा, अपनी धरती पर अजनबी बन जाना दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक है। एलजी प्रो. अशोक कौल की किताब कश्मीर-नेटिविटी रीगेंड के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। जम्मू विश्वविद्यालय के राजेंद्र सिंह सभागार में हुए कार्यक्रम में सिन्हा ने कहा कि अपनी धरती पर अजनबी बन जाना दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक है। अपनी जड़ों से उजड़ जाने का दर्द आज भी बेघर हुए परिवारों की रगों में कांटों की तरह चुभता है।

तकनीकी महाशक्ति बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम!

अमेरिका के नेतृत्व वाले एलीट अलायंस 'पैक्स सिलिका' में हुआ शामिल

नईदिल्ली। भारत ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान भारत आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक तकनीकी गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल हो गया। यह नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुआ।

इस कदम का मकसद ज़रूरी मिनरल्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और तेज़ी से विकसित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में आपसी सहयोग को गहरा करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अमेरिका के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग और राजदूत सर्जियो गोर ने दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में पैक्स सिलिका घोषणा पर साइन किए, जिससे नई दिल्ली इस ग्रुप में शामिल हो गई।

यह नई दिल्ली और वाशिंगटन द्वारा दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को मज़बूत करने के लिए एक ट्रेड डील पर साइन करने के बाद भी हुआ है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से जुड़े तनाव के दौर के बाद।

पैक्स सिलिका क्या है और यह क्या करता है? पैक्स सिलिका एक अमेरिका-लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसे दिसंबर 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने और नॉन-अलाइंड देशों पर निर्भरता कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह ज़रूरी मिनरल्स, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और तेज़ी से विकसित हो रहे एआई सेक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करना चाहता है, जिसका मकसद एक सुरक्षित और मज़बूत ग्लोबल सिलिकॉन और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना है।

अमेरिका के अलावा, पैक्स सिलिका में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इज़राइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

जैकब हेलबर्ग के अनुसार, 20वीं सदी को तेल और स्टील ने चलाया, जबकि 21वीं सदी कंप्यूटर पर चलती है, जो लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स पर निर्भर हैं।

इस कदम से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच ज़रूरी मिनरल्स और सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज़ी से आगे बढ़ते क्षेत्र में आपसी सहयोग गहरा होने की उम्मीद है, जिसका मकसद एक सुरक्षित और मज़बूत ग्लोबल सिलिकॉन और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना है।

पैक्स सिलिका को भरोसेमंद देशों के बीच एक शेयर्ड फ्रेमवर्क बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि भविष्य के एआई और टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप किए जा सकें। यह पहल पूरी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में फैली हुई है, एनर्जी रिसोर्स और ज़रूरी मिनरल से लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एआई मॉडल तक। सदस्य देश खुशहाली, टेक्नोलॉजिकल तरक्की और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का वादा करते हैं।

लंबे समय का मकसद टेक्नोलॉजी से चलने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है ताकि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्थिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें और उभरती एआई-पावर्ड ग्लोबल अर्थव्यवस्था से फ़ायदा उठा सकें।

पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन एआई को एक बदलाव लाने वाली ताकत के तौर पर पहचानता है जो ग्लोबल मार्केट को नया आकार दे रही है। इसमें कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्नोलॉजिकल क्रांति तेज़ हो रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से बना रही है और ग्लोबल सप्लाई चेन को फिर से बना रही है।

अमेरिका-पाकिस्तान दोस्ती पर जयराम रमेश का तंज

मोदी की डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो चुकी है

नईदिल्ली। एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि स्वघोषित विश्वगुरु दुनिया को संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से ज्ञान देने में व्यस्त हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, गुरुवार को वाशिंगटन डीसी में बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए, रमेश ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध पहले की तरह ही मजबूत हैं।

रमेश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को 22 अप्रैल, 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने के लिए वैश्विक मंच पर कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी है, और इसे मोदी सरकार की कूटनीति पर एक निराशाजनक टिप्पणी बताया, जिसे किसी भी तरह की तोड़-मरोड़ से मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में हाल के घटनाक्रमों से यह स्पष्ट है। रमेश ने आगे कहा कि जब यह सब हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नारों और संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि मजबूत करने और कॉरपोरेट जगत के नेताओं को उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए मजबूर करने में व्यस्त थे।

एक्स पोस्ट में कहा गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का रोमांस बेरोकटोक जारी है। कल वाशिंगटन डीसी में एक बार फिर इसका प्रदर्शन देखने को मिला। 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने के बावजूद पाकिस्तान को विश्व मंच पर कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, यह मोदी सरकार की कूटनीति पर एक निराशाजनक टिप्पणी है जिसे किसी भी तरह की चालाकी से मिटाया नहीं जा सकता। यह बिल्कुल स्पष्ट है। इस बीच, स्वघोषित विश्वगुरु अपने संक्षिप्त नामों के माध्यम से दुनिया को ज्ञान देने और सीईओ को अपना हाथ थामकर उनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मजबूर करने में व्यस्त हैं। यह मोदी शासन है, जो भारत को नुकसान पहुंचाने वाला अधिकतम दिखावा है।

भारत एआई इम्पैक्ट समिट, ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार करता है, जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय (सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए सुख) के राष्ट्रीय दृष्टिकोण और मानवता के लिए एआई के वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप है। यह शिखर सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शासन, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित हो रही एक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है।

अदृश्य राजनीतिक दबाव में हैं प्रधानमंत्री : राहुल गांधी

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में इस्तेमाल किए गए अपने जिउ-जित्सु के उदाहरण को समझाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक पकड़ और दबाव में फंसे हुए हैं, जो जनता को दिखाई नहीं देते। ङ्क पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए गांधी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने संसद में अपने भाषण में जिउ-जित्सु का उदाहरण क्यों दिया। मैंने पकड़ और दबाव का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये जिउ-जित्सु खेल में होते हैं और इसी तरह प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में भी इसी तरह के तरीके मौजूद हैं, लेकिन जनता को दिखाई नहीं देते।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि राजनीतिक पकड़ और दबाव ज्यादातर छिपे रहते हैं। आम आदमी उन्हें देख नहीं पाता। और यह देखने के लिए कि दबाव कहां लगाया जा रहा है, आपको ध्यान से देखना होगा। गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दबावों के बीच फंसे हुए हैं। अमेरिका में अडानी मामले और एपस्टीन मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि कई भारतीय नाम उन फाइलों से जुड़े हैं जिन्हें अभी तक जारी नहीं किया गया है।

गांधी ने कहा कि एक तरफ चीन हमारी सीमा पर बैठा है, और दूसरी तरफ अमेरिका। और हमारे प्रधानमंत्री इन दोनों के बीच फंसे हुए हैं। वे फँसे हुए हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि वित्तीय समर्थन से कायम है और उस छवि पर नियंत्रण भारत के बाहर के लोगों के हाथों में है। गांधी ने दावा किया कि नीतिगत फैसलों का असर किसानों और कपड़ा क्षेत्र पर पड़ सकता है, और आरोप लगाया कि भारत को अमेरिका से आयात बढ़ाना पड़ सकता है।

उन्होंने डेटा प्रबंधन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। तथ्य यह है कि हमारा डेटा नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका की अमेरिकी कंपनियों को मामूली कीमत पर सौंपा जा रहा है। और मेरी बात याद रखिए, हम डेटा कॉलोनी बनने जा रहे हैं। गांधी ने सवाल उठाया कि भारत अमेरिका के साथ डेटा, कृषि और उद्योग से संबंधित समझौते क्यों करेगा, और कहा कि इसका जवाब प्रधानमंत्री पर लगाए गए दबाव और दबाव में निहित है।

खेल
प्रमुख समाचार

एशिया कप : श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचा भारत

बैंकॉक। कप्तान राधा यादव ने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए भारत ए की टीम को शुक्रवार को यहां श्रीलंका ए पर पांच विकेट से जीत दिलाकर वुमैन्स राइजिंग स्टार्स टी20 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन यह उस पर भारी पड़ गया। राधा की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने उसके बल्लेबाजी लाइन-अप को तहस-नहस कर उन्हें 118 रन पर आउट कर दिया। बाएं हाथ की स्पिनर राधा ने 19 रन देकर चार विकेट लिए। राधा को एक और बाएं हाथ की स्पिनर तनुजा कंवर (20 रन देकर दो विकेट) और लेग स्पिनर प्रेमा रावत (नौ रन देकर दो विकेट) का अच्छा साथ मिला।

श्रीलंका के लिए सलामी बल्लेबाज संजना काविंदी (31 रन) शीर्ष स्कोरर रहीं। 10वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर दो विकेट पर 71 रन था। लेकिन इसके बाद वे भारतीय स्पिनरों का सामना नहीं कर सकीं और बचे हुए आठ विकेट नौ ओवर में 47 रन के अंदर गंवा दिए। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी भागीदारी काविंदी और साथी सलामी बल्लेबाज हंसिमा करुणारत्ने (14) के बीच 36 रन की साझेदारी रही।

लक्ष्य का पीछा करते समय भारत ने एक समय 21 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। टीम के लिए वृंदा दिनेश 42 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। लेकिन राधा ने बल्लेबाजी में योगदान करते हुए 18 गेंदों पर सात चौकों की मदद से नाबाद 31 रन बनाए जिससे भारत ने 13.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। फाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 316 अंक चढ़ा निफ्टी 25571 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से मिलेजुले रुझान के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार (20 फरवरी) को बढ़त में बंद हुए। एक दिन पहले बड़ी गिरावट के बाद बाजार में निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिली। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गिरावट के साथ 82,272 अंक पर खुला। शुरुआती कारोबार में सपाट चाल के बाद दोपहर में यह 600 अंक तक चढ़ गया था। अंत में 316.57 अंक या 0.38 प्रतिशत की बढ़त लेकर 82,814.71 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 गिरावट लेकर 25,406 पर खुला। हालांकि, खुलने के बाद इंडेक्स में थोड़ी बढ़त देखने को मिली और कारोबार के दौरान यह 25,663 अंक तक चला गया था। अंत में 116.90 अंक या 0.46 फीसदी की बढ़त के साथ 25,571 पर बंद हुआ।

क्वालकॉम और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली। अमेरिकी चिप कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की शुक्रवार को जानकारी दी। इसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम में क्वालकॉम ऑटोमोटिव मॉड्यूल का विनिर्माण करेगी। कंपनियों की ओर से शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान के अनुसार, इस सहयोग के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के वैश्विक मॉड्यूल विनिर्माण साझेदार नेटवर्क में शामिल हो गई है जिसका उद्देश्य मॉड्यूलर ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म की बढ़ती वैश्विक मांग को समर्थन देना है। बयान में कहा गया, मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज अपने क्वालकॉम ऑटोमोटिव मॉड्यूल उत्पादों का विनिर्माण भारत में जागीरोड (असम) में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी सेमीकंडक्टर असेम्बली एवं परीक्षण इकाई में करेगी।

1 अप्रैस से बदल जाएंगे इनकम टैक्स फॉर्म के नंबर

नईदिल्ली। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2026 से इनकम टैक्स फॉर्म के नंबर बदल दिए जाएंगे। जो 1962 के नियमों के तहत छह दशक पुराने फ्रेमवर्क की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव टैक्स कम्प्लायंस को आसान, ज़्यादा डिजिटल और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ड्राफ्ट रूल्स के तहत नोटिफाइड फॉर्म मैट्रिक्स के अनुसार फॉर्म 16, फॉर्म 16 ए, फॉर्म 24क्यू, फॉर्म 26क्यू, फॉर्म 27क्यू और फॉर्म 26एएस जैसे फॉर्म के नए नंबर होंगे। मौजूदा फॉर्म 16, जो एक्ट के सेक्शन 395 के तहत सेक्शन 392 के तहत किसी कर्मचारी को दी गई सैलरी पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के लिए सर्टिफिकेट है, उसे फॉर्म 130 के रूप में फिर से नंबर दिया जाएगा। इसमें सेक्शन 393(1) के तहत बताए गए सीनियर सिटिजन की पेंशन या ब्याज इनकम के लिए सर्टिफिकेशन भी शामिल है, जैसा भी लागू हो।

अमेरिका-ईरान तनाव से उछला कच्चा तेल

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ छह महीने के उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे तेल बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। 20 फरवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) लगभग 67 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है। पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट 1.9% की बढ़त के साथ 71.66 डॉलर पर बंद हुआ था और डब्ल्यूटीआई भी 1.9% चढ़कर 66.43 डॉलर पर पहुंच गया था। पिछले दो सत्रों में कुल मिलाकर 6-7% की तेजी दर्ज की गई है, जो जनवरी के अंत के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गेमचेंजर हैं समझौते

डॉ जयंती लाल भण्डारी

हाल ही में इनवेस्टमेंट इनफॉरमेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर लगाए गए टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के बाद भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के तेजी से बढ़ने और निर्यात की नई संभावनाएं बनी हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि टेक्सटाइल के टैरिफ में कमी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक व्यापार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इससे भारतीय टेक्सटाइल्स निर्यातकों को राहत मिलेगी और उनकी लागत प्रतिस्पर्धा बेहतर होगी।

ऐसे में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में टेक्सटाइल्स निर्यात से होने वाली कमाई में 8 से 11 प्रतिशत तक और टेक्सटाइल कंपनियों के मुनाफे में लगभग 9।5 प्रतिशत की बढ़त की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ में कटौती के अलावा भारत-यूरोप मुक्त व्यापार समझौते और अन्य द्विपक्षीय समझौतों में टेक्सटाइल्स सेक्टर को दी गई अहमियत की वजह से आने वाले समय में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इसी आधार पर रेटिंग एजेंसी ने अब टेक्सटाइल सेक्टर का आउटलुक 'नेगेटिव' से बढ़ाकर 'स्टेबल' कर दिया है।

गौरतलब है कि 13 फरवरी को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते और अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों से आगामी पांच वर्षों में रोजगार के 70 से लाख अधिक नए अवसर पैदा होंगे।

सरकार का लक्ष्य टेक्सटाइल सेक्टर के कारोबार को 2026 तक वर्तमान 152 अरब

डॉलर से बढ़ाकर 350 अरब डॉलर और निर्यात को वर्तमान 37।8 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर मूल्य तक पहुंचाने का है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारत को भी अमेरिकी धागे और कपास से बने कपड़ों पर शुल्क में उसी तरह की छूट हासिल होगी,

जैसी बांग्लादेश को हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में मिली है। इस समझौते के मुताबिक बांग्लादेश से अमेरिका में आयात पर पारस्परिक शुल्क घटकर 19 फीसदी रह जाएगा। अगर कपड़ा अमेरिकी कपास और मानव निर्मित फाइबर से तैयार होता है तो अमेरिकी बाजार में उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

अभी बांग्लादेश से अमेरिका को निर्यात हो रहे कपड़ों पर 31 फीसदी आयात शुल्क लगता है, जिसमें सबसे पसंदीदा देश पर लगने वाला 12 फीसदी आयात शुल्क और 19 फीसदी पारस्परिक शुल्क है। अमेरिकी फाइबर इस्तेमाल होने पर पारस्परिक शुल्क खत्म हो जाएगा और कुल 12 फीसदी आयात शुल्क लगेगा।

ऐसे में अब भारत भी अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते में बांग्लादेश जैसी ही टैरिफ व्यवस्था वाले कर समझौते की डगर पर आगे बढ़ा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौते भारत के टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में तेज वृद्धि लाएंगे।

केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जिस तरह अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं, उससे भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वस्तुत: इन बजट प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक वस्त्र निर्माण का हब बनाना, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के तहत 'रेशा से फैशन' तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसमें प्राकृतिक रेशों और मानव निर्मित फाइबर के लिए 'राष्ट्रीय फाइबर योजना' शामिल है। नए बजट में सात पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क को खास प्राथमिकता दी गई है।

विश्वास निर्माण गौरव विष्णु का सुशासन

समावेशी विकास और जनकल्याण का आधार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

महिला सशक्तीकरण

महतारी वंदन योजना
68.39 लाख
महिलाओं को 24 किस्तों में कुल
₹15,588.36 करोड़
अंतरित

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
37 लाख
से अधिक महिलाएं लाभांवित

महतारी सदन
368 महतारी सदनों
के निर्माण हेतु
₹108.78 करोड़
स्वीकृत

युवा सशक्तीकरण

आयु सीमा
सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में
5 वर्ष की छूट

पदों पर भर्ती
लगभग 32,000
रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

उद्यम क्रांति योजना
स्वरोज़गार के लिए
50% सब्सिडी
पर ब्याज मुक्त ऋण

किसान कल्याण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
26 लाख
किसान लाभांवित

धान
₹3100/क्विंटल और
21 क्विंटल/एकड़
की दर से धान खरीदी

बैंक राशि
दो वर्षों में किसानों के खातों में
₹1.50 लाख करोड़
से अधिक की राशि अंतरित

औद्योगिक विकास

नई औद्योगिक नीति लागू
₹7.83 लाख करोड़
से अधिक का मिला निवेश प्रस्ताव

औद्योगिक हब
नया रायपुर
बन रहा औद्योगिक हब

चिप यूनिट
₹1100 करोड़
की लागत से चिप यूनिट स्थापित

26 लाख
से अधिक आवास स्वीकृत

400 से अधिक
प्रशासनिक सुधार से निवेश की राह आसान

पारदर्शिता लाने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन

₹51,080 करोड़
से रेल परियोजनाओं का हो रहा क्रियान्वयन

₹40 हज़ार करोड़
से अधिक लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का हो रहा विकास

संवाद-46967/186

सरल, सहज और उदार व्यक्तित्व वाले माननीय मुख्यमंत्री
श्री विष्णु देव साय जी को हार्दिक शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.